is a matter that the Railway Ministry must examine first, because it will amount to discrimination, for the same offence is cognisable when it concerns some other person or even Government Property, other then railway property, but when it concerns railway property it is not cognisable. Whether it is proper within the framework of the common criminal law is the only point which the Railway Ministry and the Government have to examine. Otherwise, I do not see any objection to this Bill as such and, therefore, I support it.

Shri Rane (Buldana): Sir, I rise to support the Bill. I do not agree with the view which has been expressed by those Members who oppose this Bill. In my opinion, offences against railway property have gone up. The destruction of railway property is going on on a very large scale.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member will continue his speech the next day. Now Shri Prakash Vir Shastri.

14.59 hrs.

MOTION *RE* GOLD CONTROL

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब 1963 में स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, तो उस समय भी इसी प्रकार की चर्चा इस सदन में कर के मैंने सरकार से कहा था कि उसका यह कदम उचित नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, कि जो बात उस समय मैंने अ र वि रोधी दलों ने कही थी, उस बात को आज सत्तारूढ़ दल भी अनुभव कर रहा है। इसे के अतिरिक्त केवल विरोधी दलों या सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यह आवाज उठ रही थी कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहि ए ।

सरकार ने इस बहस के प्रारम्भ होने से लगभग चौबीस घंटे पूर्व चौबिस कैराट तक के गहने बनाने का निर्णय लेकर "सुबह का भूला शाम को घर आया" की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। यह बात समझ में नहीं आई जब इस प्रकार की घोषणा कर ही दी कि अब 22 कैरट या 24 कैरट के आभूषण बनाए जा सकेंगे तब सरकार नाक सीधे न पकड़ कर पीछे से पकड़ने का यत्न क्यों कर रही है। जब नाचने के लिए सरकार उतरी तो फिर घूंघट निकाल कर नाचना कहां की अक्लमंदी है ? मैंने इस कानून को काला कानून और हत्यारा कानून क्यों कहा इस की व्याख्या भी मैं करना चाहूंगा। मैंने इस कानून को हत्यारा इसलिए कहा कि इस कानून की वजह से देश में लगभग 250 स्वर्णकारों को आत्म-हत्या का शिकार होना पड़ा। इस काले कानून की वजह से दस हजार बच्चे जो स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा का सिल-सिला टूट गया। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लाखों ही परिवार इस तरह के थे जो तबाह हो गए और जिनको इधर उधर भीख मांगनी पड़ी।

15 hrs.

सरकार ने कल अगर मगर लगा कर के जो यह कैरट की छूट दी है मुझे समझ में नहीं आता है कि यह तब क्यों दी जब सारे देश में इस के ऊपर तूफान खड़ा हुआ? जब संसद् भवन के सामने आमरण अनशन प्रारम्भ हो गए, प्रति दिन पांच पांच और छः छः सौ की संख्या में गिरफ्तारी होने लगी? अब जो सरकार ने इन आन्दोलनों के बाद और इस प्रकार का तूफान उठने के बाद यह निर्णय लिया है, क्या इस से यह समझा जाय कि सरकार हर राष्ट्रीय प्रश्न को इसी भाषा का उपयोग होने पर हल करना चाहती है ? सरकार इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इसी प्रकार आन्दोलन करने के लिए देश को प्रोत्साहन दे रही है ? एक महीना पहले अगर सरकार ने यह निर्णय ले लिया होता तो क्या इस में हानि थी ? सरकार ने गालियां भी खाईं और उस के बाद नाक भी रगड़ी। इन दोनों में कौन सी अक्लमंदी हुई ?

मैं एक बात जो विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि जब इस स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्दर छूट देने की

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

घोषणा कल प्रधान मंत्री ने की, तो एक बात समझ में नहीं आई कि जब यह कानून लागू हुआ था उस समय उस की घोषणा की थी वित्त मंत्री ने और अब जब इस कानून में छूट देने का प्रश्न आया तो इसकी घोषणा की प्रधान मंत्री ने। जिस समय पाप लगने का प्रश्न था उस समय तो वित्त मंत्री को आगे कर दिया और जिस समय वाहवाही लेने का प्रश्न आया तो प्रधानमंत्री आगे आ गई। अब वित्त मंत्री कहां चले गये? यह घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न है जो सामान्य दिमागों के अन्दर चक्कर काट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अव्यावहारिक कानून आधा तो लगभग उसी दिन समाप्त हो गया था कि जब टी० टी० कृष्णमाचारी ने पुराने ज़ेवरों को फिर से बनाने की छूट दे दी थी। रहा सहा कल प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद समाप्त हो गया। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि 1963 के पहले की स्थिति जो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने से पहले थी, सरकार उस स्थिति को वापस लाने में क्यों हिचकिचाती है?

इस देश में जैसी कि एल० पी० सिंह कमेटी की रिपोर्ट कल प्रधान मंत्री ने सदन की टेबल पर रखी, उन के हिसाब से, लगभग 3 लाख स्वर्णकार हैं और जन गणना के हिसाब से उन की संख्या 5 लाख के लगभग बैठती है। लेकिन स्वर्णकार संगठनों का कहना है कि उन की संख्या लगभग 40 लाख की है। जो भी हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो स्वर्णकारों को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने पर लाइसेंस दिये थे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उन की संख्या 2 लाख 7 हजार 747 बैठती है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी के स्वर्णकार जो एल० पी० सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनसार रह जाते हैं या 1961 की जनगणना के अनुसार रह जाते हैं, उसमें जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिए, उन की क्या स्थिति अब होगी? वह सोने का काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन में सरकार क्यों इनको उलझाकर रखना चाहती है? जब कैरेट की छूट दे ही दी तो बाकी सुविधाओं को भी सरकार क्यों नहीं दे रही है? गांधी जी इस बात को बार बार कहा करते थे कि गलती करने के बाद उसे सुधारना बड़प्पन का चिन्ह होता है। लेकिन यह सरकार गलती करने के बाद गलती को सम्भालने में बड़प्पन समझती है। ऐसी स्थिति पता नहीं कब तक सरकार रखना चाहती है?

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने से इस देश को कितनी भयंकर हानि हुई उस के भी कुछ मैं आंकड़े देना चाहुंगा। स्वर्ण नियंत्रण जिस समय लागू नहीं हुआ था उस से पहले सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है लगभग 27 करोड़ रुपया वार्षिक इनकम टैक्स की शकल में सरकार के अपने आंकड़, के अनुसार आता था, इसी प्रकार से जो स्टट ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सरकार को सब मिलाकर के लगभग 100 करोड़ रुपये इन से मिलते थे राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को। साढ़े तीन साल के अन्दर 350 करोड़ रुपये की हानि तो सरकार ने इस प्रकार स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू कर के की। इस के अतिरिक्त 30 से लेकर 50 करोड़ रुपये की हानि उन को जो मदद दी, या उन के बच्चों को शिक्षा के नाम पर या रिहैबिलिटेशन के नाम पर दिया। देश आपसे पूछता है कि यह 4 अरब रुपये की हानि जो इस ग़रीब देश को हुई, इस का प्रायश्चित कौन करेगा? 250 हत्यायें जो इस देश में हुईं इन का प्रायश्चित कौन करेगा? यह कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज सरकार को देना होगा। जिस समय यह स्वर्ण नियंत्रण

अधिनियम लागू हुआ था तत्कालीन वित्त मंत्री ने तीन बातें कही थीं कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से क्या क्या लाभ होंग । पहला लाभ यह बताया था कि सोना ो चोरी से आता है उस का तस्कर व्यापार एक जाएगा । दूसरी बात यह कही थी कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू हो जाने से सोने की अन्तर्राष्ट्रीय दरं साढ़े बासठ रुपये तोले है, वह भारतवर्ष में होजायेगी । तीसरी बात यह कही थी कि जनता का सोने से मोह छूटेगा और जो सोना घरों में बेकार पड़ा हुआ है वह बाहर आ जाएगा और काम में लग जाएगा । यह तीन बातें कही थीं । मैं ईन पर भी संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा ।

जहां तक तस्कर व्यापार रोकने का सम्बन्ध है वह रुका या बढ़ा, इस के सम्बन्ध में मैं स्वयं न कह कर के एल ० पी० सिंह कमेटी की रिपोर्ट जो कल प्रधान मंत्री ने सदन की टेबल पर रखी थी उस की तरफ ध्यान दिलाऊंगा । वह इस के लिए पर्याप्त प्रमाण है । पहले वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 13 सितम्बर को मद्रास के अन्दर यह कहा कि तस्कर व्यापारियों ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद नये ढंग अपना लिए हैं । वर्तमान वित्त मंत्री ने भी 16 मई को कलकत्ते की प्रैस कांफ्रेंस में यह कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद तस्कर व्यापार नहीं रुका । अब तस्कर व्यापार से सोना कितना आया, अब इस के भी उदाहरण सुनिये । एन्फोर्समेंट ब्रांच या जो कस्टम्स एक्सपर्टस हैं, उन का कहना है कि जितने चोरी से सामान लाने वाले व्यक्ति हैं उन में से 17 से 20 इस प्रकार के हैं जो हमारे हाथ से बच कर के निकल जाते हैं, । कठिनाई से एक व्यक्ति को हम पकड़ पाते हैं । अब जो पकड़े जाते हैं, उन के द्वारा कितना सोना मिला, इस से अनुमान लगाइये कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बा तस्कर व्यापार बढ़ा है या घटा है । यह सरकारी आंकडे हैं कि जितना सोना सरकार ने पकड़ा सन् 1963 में जिस सन् के अन्दर यह कानून लागू हुआ था, वह था 1 हजार 33 किलोग्राम 1964 में जो पकड़ा सरकार ने वह था 1532 किलोग्राम और 65 में यह बढ़ कर के 2301 किलोग्राम हो गया । इस तरह से जो सरकार सोना पकड़ती रही है उस की मात्रा जब बराबर बढ़ती रही है तो सोने का तस्कर व्यापार बराबर हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ा, उस में कुछ कमी नहीं हुई एल० पी० सिंह कमेटी की रिपोर्ट स्वयं इस बात को कहती है दबे हुए शब्दों के अन्दर कि कुछ साल के अन्दर लगभग 1 अरब रुपये का सोना इस देश में तस्कर व्यापारियों के माध्यम से आता है । 1 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा की हमें हानि करनी पड़ती है और करनी भी क्यों न पड़े जब स्थिति इस प्रकार की है कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव है 53.58 रुपये और तस्कर लोग जो लाते हैं सोना वह 70 से लेकर 80 रुपये तक प्रति 10 ग्राम के हिसाब से लाते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अवमूल्यन के बाद यह रकम बढ़ गई है ।.... (**व्यवधान**)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हो सकता है इसमें वित्त मन्त्री के आंकड़ों को सही माना जाय । (व्यवधान) सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव मैंने बताया...

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अवमूल्यन के बाद 53 रुपये कुछ पैसे नहीं हो सकता ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : 100 करोड़ रुपये की जो रकम उन्होंने बतायी थी उसके लिए मैंने कहा ठीक है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इन्होंने कहा कि 53 रुपये कुछ पैसे उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत है वह 53 रुपये कुछ पैसे हो नहीं सकती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वित्त मन्त्री सही बता रहे हैं । वह जो 100 करोड़ का आंकड़ा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मैंने कहा उसके लिए वह यह कह रहे हैं कि अवमूल्यन के बाद वह 100 करोड़ के लगभग बठता है। आप जो चर्चा कर रही हैं वह सोने के अन्तर्राष्ट्रीय भावों की चर्चा कर रही हैं।

मैं पीछे यह बात कह रहा था कि सोने का अन्तर्राष्ट्रीय भाव अवमूल्यन से पूर्व था 53 रुपये 58 पैसे। तस्कर व्यापारी 70 से 80 रुपये में लाते थे और हिन्दुस्तान में ला करके 145 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बेचते थे। तो जब तक सोने का भाव गिर कर अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोना भारत में नहीं आयेगा यह मामूली दिमाग रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। तब तक हिन्दुस्तान में सोने का तस्कर व्यापार कैसे रुक सकता है?

अब हिन्दुस्तान के चारों ओर जो देश हैं उनमें जो सोने का भाव है वह मैं थोड़ा आप के सामने रखता हूं। अरब कण्ट्रीज के अन्दर 70 रुपये तोला। अफ्रीकी राष्ट्रों में 80 रुपये तोला। लंका में 70 रुपये, बर्मा में 80 रुपये, पाकिस्तान में 121 रुपये तोला और उस समय भारतवर्ष में सोने का भाव था 180 रुपये तोला। अब जब ऐसी स्थिति है तो फिर सरकार कैसे अधिकारपूर्वक कह सकती है कि देश के अन्दर सोने का तस्कर व्यापार वह किसी प्रकार से रोक सकेगी।

वित्त मन्त्री ने एक बात यह भी कही थी कि इस स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के लागू होने के बाद देश में सोने की दर घट जायगी अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोना देश में बिकने लगेगा। लेकिन स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू होने के बाद देश में सोने का भाव बढ़ा है—सोने का भाव कम नहीं हुआ। 1963 में सोने का भाव 95 रुपये से लेकर 114 रुपये प्रति 10 ग्राम था लेकिन 1964 में वह भाव बढ़ कर 125 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया और 1966 में वही भाव बढ़ कर 142 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान में सोने के भाव घटे। सरकार के इस अधिनियम के लागू होने के बाद सोने के आयात की स्थिति कभी नहीं सुधरी और न ही अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर सोना हिन्दुस्तान में कभी नहीं बिक सका।

दूसरी बात सरकार यह समझती थी कि भारतवर्ष में कुछ सोने की खानें हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सकेंगे। लेकिन वित्त मन्त्री ने अभी पीछे 12 सितम्बर 1963 को एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो कोलार वगैरह की सोने की खानें हैं उनसे जो सोना निकलता है वह भारतवर्ष में पड़ता है 124 रुपये प्रति 10 ग्राम। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सोने का भाव 53 रुपये 58 पैसे है। लिहाजा अपने देश में जो सोना निकलता है वह भी महंगी कीमत पर आकर पड़ता है।

तब इस कानून के लागू होने से तीसरा लाभ यह बताया गया था कि जो सोना घरों में बेकार पड़ा हुआ है वह बाहर आ जायगा। उपाध्यक्ष जी, यह बड़े उपहास की बात है। जिस समय यह कानून इस नादान सरकार ने लगाया था उस समय चीन का आक्रमण हो कर चुका था चीनी आक्रमण के बाद सारे देश में एक राष्ट्रीय भावना फैली हुई थी। उस समय लोग अपने आप सोना उतार कर राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे रहे थे क्योंकि देश की रक्षा का प्रश्न उस समय उपस्थित था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि न केवल सोना दे रहे थे बल्कि हिन्दुस्तान के तत्कालीन प्रधान मन्त्री और एक-दो अन्य मन्त्रियों को जनता ने सोने से तोला भी था। लेकिन इस नादान सरकार ने क्या किया? इसने सोचा कि यह मुर्गी रोज एक सोने का अण्डा देती है क्यों न इसके पेट को चीर कर सारे अण्डे एक साथ ही निकाल लिये जायं? परिणामस्वरूप सरकार ने गोल्ड कण्ट्रोल एक्ट लागू किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहले सोना देते थे उन्हें यह विश्वा

था कि आज सोना दे दो इससे देश की इज्जत बच जायेगी फिर बाद में बाजार से सोना खरीद लेंगे, जब उनको यह पता चला कि आज जो सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे कुछ दिनों के बाद वह सोना सोने की शक्ल में नहीं 14 कैरेट के ताम्बे की शक्ल में मिलेगा तब ही इस सरकार को देश में सोना मिलना बन्द हो गया। हार कर सरकार ने कुछ और उपाय अपनाये—गोल्ड बाण्ड चालू किया। उसकी क्या स्थिति रही? वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीन तरह के गोल्ड बाण्ड सरकार ने जारी किये। पहला गोल्ड बाण्ड 1977 तक का जो साढ़े छः प्रतिशत के हिसाब से मिलना था उससे जो सोना मिला वह सब मिला कर 16,092 किलोग्राम था दूसरा गोल्ड बाण्ड 1980 तक का 7 प्रतिशत से मिलना था—इसमें कुल 6,146 किलोग्राम सोना मिला। इसके बाद सरकार ने हार कर नेशनल डिफेन्स बाण्ड की स्कीम जारी की उसमें यह था कि जितने प्रतिशत शुद्ध सोना होगा उतने प्रतिशत शुद्ध सोना 1980 में वापस किया जायगा। इसमें जो सोना मिला वह 13,558 किलोग्राम था। यदि मैं इस रकम को रुपयों में कहूं तो यह कह सकता हूं कि सरकार को यह अनुमान था कि उनको 100 करोड़ रुपये का सोना मिल जायगा, ऐसी सम्भावना सरकार को थी लेकिन कुल मिला कर सरकार को 60 करोड़ 13 लाख रुपये का सोना मिल पाया। इससे आप अनुमान लगा लीजिये कि सरकार पर से जनता का कितना विश्वास उठ गया है। क्या देश में सोना नहीं है? ऐसी बात नहीं। रिजर्व बैंकके ही अनआफोशियल आंकड़े इस बात के गवाह हैं रिजर्व बैंक का कहना यह है कि हिन्दुस्तान में लगभग 4 जार करोड़ रुपये का सोना है यानी 40 अरब रुपये का सोना जब कि सरकार को इन तीनों गोल्ड बाण्ड स्कीमों में कुल मिला कर 60 करोड़ रुपये का सोना सरकार को मिल सका। अब इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार पर से जनता का कितना विश्वास हट चुका है।

उपाध्यक्ष जी, एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ सोना ऐसा भी है, सम्भव है रकार उसके आंकड़े नहीं देना चाहे, जिन्होंने अपने आप घोषित किया है। सरकार उनके साथ वचनबद्ध है कि हम तुम्हारे सोने को नहीं बतायेंगे, लेकिन इससे बड़ा सरकार के दिवालियापन का सबूत और देना चाहूंगा। जिस समय मुद्रा-अवमूल्यन की चर्चा आई, उस समय रेल मन्त्री पाटिल जो कि सबसे बड़े पहलवान केबिनेट में माने गये, उनको अपनी बचत के लिये सरकार ने खड़ा किया। लेकिन उन्होंने सरकार के दिवालियापन का सबूत देते हुए कहा कि अगर हमारे कोष में 5 अरब रुपये का सोना होता तो शायद रुपये की कीमत न घटानी पड़ती। आप अन्दाजा लगाइये, हिन्दुस्तान की सरकार ने 48 अरब रुपये के नोट चला रखे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के कोष में 5 अरब रुपये का सोना भी नहीं है। फिर सरकार कैसे विश्वास करती है कि जनता सरकार को गोल्ड बांड स्कीम में पैसा लगायेगी या सरकार को और पैसा देगी? जब सरकार इतना विश्वास खो चुकी है और जब जनता का पूरा विश्वास सरकार पर हो गया है, तब सरकार बारबार अपनी नई नई योजनायें प्रस्तुत करती है, उसका कोई लाभ सरकार को नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी कागजी मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहा। मूल्य ही नहीं रहा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है बल्कि स्थिति यह आ गई है कि अब किसान, कल जो आपने घोषणा की है, सम्भव है कि इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो लेकिन आज तक की स्थिति इस प्रकार की थी कि किसान अपनी पैदावार बाजार में लाने से हिचकिचाता था, क्योंकि पहले जब किसान अपनी पैदावार को बाजार में ले जाता था, तो उसके बदले सोना ले लिया करता था। लेकिन जब किसान को सोने के नाम पर तांबा मिलने लगा, उसने वह लेना बन्द कर दिया। चूंकि कागजी मुद्रा का उसकी निगाह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

में कोई मूल्य नहीं है क्योंकि पता नहीं कागजी मुद्रा किस दिन बदल जाय, इसकी क्या स्थिति हो ? नतीजा यह हुआ कि उसने अपने अनाज को ही सोना समझ लिया और अपने घर में अप : अनाज को रोकने लगा । इसमें देश में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हो गई । सरकार की इस गलत नीति से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा, यह पिछले साढ़े तीन सालों में स्वर्ण नियन्त्रण ने बता दिया ।

इसलिये उपाध्यक्ष जी मेरा अनरोध है कि वित्त मन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी इस सरकार की झूठी प्रतिष्ठा के मोह को त्यागें । कल की प्रधान मन्त्री की घोषणा ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि सरकार उचित मार्ग से किसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है, जब तक सरकार के सामने आन्दोलन न किये जायं, आमरण अनशन न किये जायं, 500—600 गिरफ्तारियां पालियामेंट हाउस के सामने न दी जायं, तब तक सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती । इन सब आन्दोलनों के बाद जाकर सरकार ने घोषणा की । क्या सरकार यह चाहती है कि और भी राष्ट्रीय प्रश्नों को इसी रास्ते से हल किया जाय ? इसी भाषा का उपयोग करके हल किया जाय । यह प्रश्न है—जो आज देश के सामने भी है और सरकार के सामने भी है जिसको सरकार को सोचकर हल करना पड़ेगा ।

दूसरी बात आज बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि अब जब कि यह निर्णय ले लिया या है कि 24 कैरेट के आभूषण, बन सकते हैं, तो फिर उसमें नाक को सीधा पकड़ने के बजाय पीछे से आकर क्यों पकड़ी है ? जो दो-चार छोटी चीजें और बाकी रह गई हैं, उनको भी हटाइये और आज साहस के साथ वित्त मंत्री चधरी इस बात की घोषणा करें । प्रधान मन्त्री तो 24 कैरेट की बात ही कह कर रह गई, लेकिन शचीन्द्र चौधरी आज इस बहस के बाद घोषणा करें कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम जो 1963 में लागू किया गया था, वह सरकार की गलती थी । सरकार से उस समय भूल हुई और अब स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को सरकार पूरी तरह से वापस लेती है । ऐसा कह करसरकार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे ।

हाउस ने चारों ओर से जो यह इस प्रकार की गड़गड़ाहट हुई है या इस प्रकार का जो वातावरण बना है इस बात का परिचय देता है कि वित्त मन्त्री को इस विषय में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये ।

एक और त, उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा . . .

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा). यह पब्लिक ओपीनियन का सिगनीफिकेन्स है

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमें यह भी निश्चय करना चाहिये कि जो इस प्रकार के अन्य राष्ट्रीय प्रश्न हैं उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की स्थिति अब न आये । सरकार पहले से ही हर प्रश्न पर समझदारी और बुद्धिमत्ता से निर्णय ले और कदम उठाये । अगर सरकार ऐसा करती है तो देश इस सरकार को साधुवाद देगा । उपाध्यक्ष जी मैं अन्तिम बात कह कर बैठना चाहता हूं कि सरकार ने अगर यह राजनीतिक खेल खेला है यह समझ कर कि इस प्रश्न के लाने से 6 महीने बाद जो एक संघर्ष राजनीतिक आने वाला है उस संघर्ष में सरकार अपनी स्थिति को बचा ले जायगी तो मैं बहुत भरे हुए शब्दों में कहना चाहता हूं कि 250 स्वर्णकारों की हत्या 10 हजार बच्चों की छूटी हुई शिक्षा लाखों बेघर परिवार जिनकी जिन्दगियां आपके इस स्वर्ण नियन्त्रण से तबाह हो गई हैं उनका अभिशाप ही इतना होगा जो आप कितना ही इस पाप का प्रायश्चित करें उस को धो नहीं सकेंगे उससे कभी उभर नहीं सकेंगे लेकिन एक तरीका है गलती करने के बाद और फिर उसका सुधार करने के बाद भविष्य में राष्ट्रीय प्रश्नों पर देश को विवश

मत कीजिये कि फिर देश को ऐसे निर्णय लेने पड़ें यहां पर प्रदर्शन करे उसको आमरण अनशन और भूख-हड़ताल के लिये विवश होना पड़े सुबह की भूली हुई सरकार अब जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको दूर करेगी और वित्त मन्त्री उसकी घोषणा करते हुए अपने साहस का परिचय देंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: It is not proper that visitors in the Gallery should make applause or make noise. It is highly unparliamentary. If it is repeated, I will have to take action.

Only Members of the House can do it.

श्री विशनचन्द्र सेठ : उपाध्यक्ष महोदय कभी आज तक इस तरह हाथ की तालियां कभी नहीं बजीं इस हाउस में यह सारे देश का प्रश्न है यह तालियां इस बात का सबूत हैं ये देश की भावनाओं का प्रतीक हैं

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Motion moved:

"That this House is of opinion that Gold Control be withdrawn and necessary steps in that, regard taken by the Government immediately."

There are some amendments. Shri Tridib Kumar Chaudhuri is not here.

Shri Karni Singhji (Bikaner): I move: That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"an adequate compensation be paid to goldsmiths who suffered losses as a result of this measure." (2)

Shri Yashipal Singh (Kairana): I move:

That for the original motion, the following be substituted, namely :—

"This House is of opinion that the restriction imposed on the manufacture of gold ornaments under the Gold (Control) Act, be withdrawn immediately and financial assistance be given to the families of those gold smiths who lost their lives while opposing this law and also that those goldsmiths who are in jails be released immediately." (3)

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): I move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the Gold Control Rules be scrapped and as a first step, the restrictions placed on the manufacture of any ornament having gold of a purity exceeding fourteen carats be withdrawn and necessary steps in that regard taken by the Government immediately by suitable amendments of the relevant Rules, while fully safeguarding the facilities now enjoyed by the self-employed goldsmiths, certified gold smiths etc." (4)

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the Government should review the working of Gold Control Rules with a view to alleviate the hardships of goldsmiths and regarding holdings of primary gold by individuals." (5)

Shri Daji (Indore): I move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that—

(a) the Gold (Control) Act and the relevant rules restricting the manufacture of ornaments above 14 carats be withdrawn forthwith;

(b) the bullion trade be nationalised;

(c) gold be made available to self-employed and certified goldsmiths; and

(d) financial and other assistance be given to the working goldsmiths to enable them to recover from the loss of livelihood caused to them by the Gold Control." (6)

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Daljit Singh is not here.

[Mr. Deputy-Speaker]

Two hours have been allotted for this discussion. I would request the hon. members to take ten minutes each.

Shrimati Vimla Devi (Eluru): If the House approves, the women members who are very much concerned may be given five minutes more.

Mr. Deputy-Speaker: She may prevail upon her leader for that. Mr. Masani.

Shri M. R. Masani (Rajkot): I rise, on behalf of my Party, to support the motion so ably moved by Shri Prakash Vir Shastri, with which one of our own colleagues, Shri Pravinsingh Solanki, is also associated, and also the amendment, the additional sentence, moved by Shri Karni Singhji of Bikaner, in regard to providing adequate compensation to goldsmiths who have suffered loss as a result of this measure.

I am right in saying that of all the perverse pieces of legislation introduced in this House during the last fifteen years, futile legislation, legislation that runs contrary to the laws of economics and human nature and has caused great harm and distress to lakhs of small people throughout the country, this Gold Control Act shines as of the first magnitude. It has done such incalculable harm and caused so much of distress out of all proportion even to the professed objectives of this measure. I am very glad that public opinion, the force of public opinion, has made this Government retreat at least partially from this misguided path.

I believe that the entire credit for this reversal goes to the goldsmiths of India. I would like to pay my tribute to this body of men, small men, men without those resources which big business commands, who have shown courage, a readiness to stand up for themselves and a capacity for sacrifice which, to its shame, big business in this country, in its timidity, has not shown all this time. I take off my hat to the group of people, the small people, who have shown what it is to stand up for what they believe in, who have shown the courage of their conviction, in contrast to Indian big business.

I would like to warn the goldsmiths that the concession that has been made yesterday by the Prime Minister is a very inadequate one. If they think that, by this concession they are going to be restored to their livelihood, they will be making a mistake. This is a very deceptive concession, made on the eve of elections. It is an election dodge, meant to throw dust in the eyes of those who are victims of this measure. Nothing but the complete repeal of this Act and its removal from the Statute Book will do justice to those concerned, whether they are peasants or they are goldsmiths.

In case the goldsmiths throughout the country are misled by this, I am very glad that in any event, in my constituency, the goldsmiths seem to be more aware. This morning my Party received a telegram from the Secretary of the Rajkot Sonachandi Karigar Mandal, which I should like to read to the House to show that at least some of them have realised what the statement made by the Prime Minister means and what it does not mean It says:

> "SUCCESS OFTEN COMES TO THOSE WHO DARE AND ACT. IT SELDOM GOES TO THE TIMID DO OR DIE. NO COMPROMISE. ADAMANT DEMAND FOR COMPLETE WITHDRAWAL OF GOLD CONTROL ACT IMMEDIATELY."

That is the demand which we put before the House. So long as the Act is on the Statute Book, we shall not be satisfied, we shall continue to agitate alongside of our goldsmith friends.

When the Act was introduced here, it was claimed that it would have three results: one was to lessen the so-called lure of gold; the second was to bring down the price of gold; and the third was to stop smuggling of gold. Let us see—two years have passed—what results have been achieved.

Has the lure of gold diminished? In that case, let the hon. Minister tell us how much gold has been surrendered to the Government to show that the lure has diminished.

Has the price gone down? The Finance Minister—it is reported in the Statesman of 26th August, 1966—made an amazing claim. He had the audacity to say:

"As a result of the Gold Control Order, the value of the rupee in terms of gold had stabilised."

I am amazed at this because the official figures tell an entirely different story. I shall now give the official figures showing the rupee price of gold on the 31st March, 1964, 1965, 1966, and on 1st September this year.

On the 31st March, 1964, before the Act was put on the Statute Book, the price of primary gold per tola was Rs. 130·61. On the 31st March, 1965, i.e. three months after the Act was put on the Statute Book, the price had risen to Rs. 142·69. On the 31st March, 1966, the rupee price was Rs. 161.23. In five months of this year, i.e. from 31st March, 1966, to 1st September the price has gone up to Rs. 167.90. In other words, in one year, the price went up by 9.25, in the second year by 12.99 and in the last four or five months by 4.14 per cent. This is a reply to the Finance Minister who has tried to mislead us. There is a close coordination between the fall in the value of the rupee and the rise in the price of gold. The plain fact is that, so long as the value of the rupee goes down, all prices rise and the price of gold also rises.

The third claim was about smuggling. Has smuggling stopped? Will the hon. Finance Minister tell us by how much smuggling has gone down? Will he give us figures of gold confiscated during the last two years to show that smuggling has stopped? We know that smuggling goes on and, so long as there is a wide margin between the Indian price of gold and the international price of gold, smuggling will go on. If on the one hand the risk of smuggling has risen, on the other hand the margin of profit has risen and people will take risks for the sake of profit.

So all the three objectives of the Gold Control Act have miserably failed. They have failed because, as I said, it is an utterly misconceived measure, going against the laws of human nature and of economics. The traditional demand for gold in this country was based on the peasants' requirements of gold as a form of secure saving. That traditional incentive has been aggravated by the inflationary policies of this Government which have made the rupee worthless. The other day a friend of mine described to me the Indian rupee as "V.C.10", and when I asked him why he called the rupee "V.C.10", he said because the Indian rupee vanishes into the air as fast as the fastest jet plane, which is called 'V.C.10"!

Therefore, there is no gold problem in India. There is only a rupee problem. The need is not for gold control; there is need for rupee control, and that is one thing which my hon. friends opposite will not control. All that they can do is to decrease the size of the one-rupee note. An announcement has been made recently that the one-rupee note is going to shrink along with its value because this will save currency paper and effect economy. This is the kind of rupee control they believe in. What is required is that the value of the rupee must not shrink; the value of the rupee must be the same; an honest rupee must be there which people accept as a form of investment.

All this was foreseen. It is not for the first time that we are saying it here. When the Bill was introduced in this House, my hon. leader, Prof. Ranga, opposed it tooth and nail. Mr. Dandeker spoke at later stages. I had also appended my Minute of Dissent to the report of the Joint Committee. We foretold what would happen. From my Minute of Dissent appended to the report of the Joint Committee, I will read a sentence. This is what I said:

"The present Bill is an exercise in futility. Worse, it reeks of hypocrisy, since even its proponents must know at the back of their minds that every one of its provisions will be violated.

"Tempted by the huge profit to be obtained from buying gold abroad and selling it here, the smuggler will continue his activity with an added margin of profit balancing the added risk of punishment.

[Shri M. R. Masani]

> Dealers and goldsmiths will continue to make 22 carat ornaments on the sly instead of making them openly and honourably so long as the women of India prefer the real article to the 14 carat variety enjoined by this law. All that this measure will succeed in doing is to tempt honest people to be dishonest. It will lesson respect for the law. It will help to create opportunities for further bureaucratic harassment and corruption."

15.29 hours

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

And this was exactly what has happened in the last two years. Now belatedly this Government comes forward and tries to buy us off with illusory concessions. What we require is a complete repeal of this measure which has failed. It has to be taken off the statute-book, and if you keep it on the statute-book it will become even more of a dead letter than it has been during the last two years.

Now, there is no doubt that in the coming years the value of the rupee is going to fall and the price of gold is going to rise. I make this forecast here that the price of gold, in spite of these measures, is going to rise for simple reason that the rupee value is going to fall; and the rupee value is going to fall because of the Fourth Plan which the cabinet has accepted and which was laid on the Table the other day.

This Fourth Plan, Shri Asoka Mehta has boasted, has not deviated in any way, according to him, from the memorandum of 1965. What an admission for a Government to make! Since the memorandum was put on the Table in 1965 under the Prime Ministership of Shri Lal Bahadur Shastri, there was a war between us and Pakistan, sensational development have taken place in our international relationships, India has gone bankrupt and our rupee has to be devalued. All this has not had the slightest effect on the wooden heads of the Planning Commission and the Cabinet, and Shri Asoka Mehta comes and says 'We have not deviated from our memorandum of 1965.' Why have not deviated? Why have you not scrapped that memorandum? Is there no need to learn the important lessons of the last fifteen years? How can you tell us that what was valid in March, 1965, is valid in September, 1966?

This Government is going to reduce the value of the rupee further, and because they will do so, the price of gold will go up. They may go on trying their best to prevent it, but they will not succeed.

These present concessions have been justified and repeat of the Act has not been accepted, because as I see, they want to keep control on bullion. Two claims have been made, the Finance Minister has said, as he has been quoted in *The Statesman* of the 28th August, 1966, that:

> "State trading in buillion will help to keep down the price of gold."

Have we ever learnt that State trading in anything keeps down the price of that commodity? Can any one item of material be shown where State trading or monopoly has kept the price down? I read in *The Times of India* of the 28th August, 1966, that a survey conducted by the National Consumer Service in Delhi shows that the Superbazar prices are higher by 2 to 20 per cent than in the free market.

An hon. Member: That has no value.

Shri M. R. Masani: The National Consumer Service is trying to serve the consumer in whom we are all interested.

Shri B. R. Bhagat: It is bogus.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I get my things from the Superbazar and the things are cheaper there.

Shri M. R. Masani: The fact is that if there is any item in which there is State trading, then the prices of that item inevitably go up. Wherever there is State trading, the prices go up. This is a law of economics. Therefore, to think or to suggest that because Government are doing State trading, the prices will come down is an entirely false claim.

Similarly, it is claimed that the control on bullion will prevent smuggling. I have already shown that, so long as the value of the rupee goes down and so long as the gold

price in India is much higher than the price of gold abroad, smuggling will go on, because there are people with an adventurous spirit, people who will break the laws for a margin of profit and who are prepared to take risks for that purpose.

In this process, as my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri has pointed out, incalculable harm or damage has been done to millions of people in this country. As many as 20 lakhs of people have been rendered unemployed. I would like to plead, in the spirit of the amendment moved by hon. friend Shri Karni Singhji, that the ameliorative measures and relief measures should not stop on the ground that these petty concessions have been made; otherwise, a new injustice will be done on top of all that has been done before.

Thousands of people have been crucified on the cross of gold, thanks to the policy of this Government. We want to tell those people that we are with them, that our solidarity with them will continue as it has done from the very start, and that our Party will not rest until this Gold Control Act is blotted out from the statute-book of India.

Mr. Chairman: Now, Shri D. C. Sharma.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I think Shrimati Tarkeshwari Sinha has got a preferential claim. She should have been called first.

Mr. Chairman: Now, Shri D. C. Sharma.

Shri Kapur Singh: The House is expected to show that much of consideration to a lady and that has been the convention also here.

Shri Ranga (Chittoor): But she does not wear any gold ornaments.

श्री विशनचन्द्र सेठ : सारे एडवांटेज इनको मिल चुके हैं ये क्या करेंगे बोल कर और ये क्या बोलेंगे ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आप जमींदार हैं, आप एडवांटेज ले लें । हम तो रैयत हैं ।

Shri D. C. Sharma: All these paladins of goldsmiths have made speeches which are more rich in eloquence than in substance. The Swatantra Party spokesman thinks that he is the sole knight wearing the armour of gold and he is going to save these goldsmiths. Here is a gentleman who has made a spiritual appeal, an administrative appeal and an appeal in terms of economies and said 'I am the man who has served the goldsmiths', and, therefore, the goldsmiths should profess their solidarity with him or with his party or whatever it is. I may tell you that human memory is very short....

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): And he depends on that?

Shri Raja Ram (Krishnagiri): And he is living on that.

Shri D. C. Sharma: Now I find these Congress Members who had opposed the Gold Control Bill at its very inception.

Shri M. R. Masani: How did my hon. friend vote?

Shri D. C. Sharma: Now I find these persons who are shedding crocodile tears over the fate of these poor goldsmiths and who have come forward to say that they are their saviours and their protectors, that thousands of goldsmiths have been crucified on the Cross of Gold and they are going to put them on a pedestal and would make much of them.

Shri Raja Ram: But did not my hon. friend vote with Shri Morarji Desai at that time? Did he not vote with him?

Shri D. C. Sharma: My hon. friend is not my conscience-keeper. I am the master of my own conscience. Who is he? Who made him my conscience-keeper?

Mr. Chairman: If the venerable professor would kindly address the Chair, he will have a little more time to develop his points.

Shri D. C. Sharma: Sometimes, these persons distract me from my main speech. I was submitting that whatever measures had been taken in regard to gold control had been taken in an above-the-board manner, in a manner which was fair and impartial and which was conducive to the good of the country. Gold control was resorted to stop smuggling. It was resorted to to lure the people away from their unhealthy and unwholesome interest in gold. It had been

[Shri D. C. Sharma]

resorted to to bring down the price of gold. All these were laudable objects. But I must say that sometimes our most praiseworthy objectives are not satisfied in this world where imperfection rules and perfection is to be found only among the Members of the Opposition Parties. I must tell you quite sincerely that I had opposed this. Here is my sister sitting to my left..

Shri Umanath (Pudukkottai): She is his leftist.

Shri Umanath (Pudukkottai): She is his voice at the meeting of the All India Congress Committee and said that this gold control had not done as much good as it should have done. I think many Members of the Congress spoke against it; I think almost everybody spoke against it. And Shri Kamaraj, our worthy and distinguished president, said, 'We have taken note of what you have said and we will do something.'.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Shri Kamaraj is not a Member of the House.

Shri D. C. Sharma: What has happened is the result of that assurance.

श्री काशी राम गुप्त : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर कोई सदस्य किसी आदमी के विरोध की बात करता है तो यहां पर आपत्ति की जाती है कि जो आदमी इस हाउस में उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार प्रेज की बात भी नहीं कही जा सकती है।

Shri D. C. Sharma: I was very respectfully submitting that we, human beings, all make mistakes.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): This is a mistake, a small mistake?

Shri D. C. Sharma: When we make speeches here, we make mistakes, and the hon. Member who interrupted me always makes mistakes. But I was submitting very respectfully that the Government did not want to defraud these goldsmiths of their genuine right of livelihood. If they had a different intention, why should they have spent Rs. 35 crores on their rehabilitation? Why should they have taken upon themselves the duty of educating their children? Why should they have taken upon themselves the duty of giving them alternative employment? The Government of India and the Government of the Congress, whatever the Opposition may say, is a kind hearted Government, is a tender-hearted Government; it is a government of the people, by the people and for the people; it is not a government of the Swatantra people, by the Swatantra people and for the Swatantra people.

Shri Umanath: It is a government to kill the people, shoot the people and fire the people.

Shri D. C. Sharma: What I was submitting was that the Government, with due regard to the economic situation in this country, taking into account the international situation and also taking note of the human situation, have come forward to reduce the rigorous of the Gold Control Order. They have gone a pretty long way in that direction and I am sure they have done something which has made people happy.

My hon. friend received a telegram today. I have been meeting persons from my own constituency; some of them are sitting in the gallery. They have come here.

Shri Bishenchander Seth: But not for the Congress.

Shri D. C. Sharma: They have given their votes for the Congress.

Shri Umanath: He is inciting people in the gallery.

Shri D. C. Sharma: I was saying that the hon. Member produced a telegram and made much of it. I can produce 150 persons here......

Shri Umanath: Produce one.

Shri D. C. Sharma: .... to prove that what the Congress Government has done has made them happy. They are going back satisfied. Of course, there are Opposition parties which will make them again start an agitation. There are people in the Opposition who will again crucify them. *(Interruptions)*. It is these persons who

crucify them. But whatever it is, Government have done well and I am sure that the Government deserve well of all.

There is one thing more. Government have drawn a distinction between goldsmiths and sarafs.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : नहीं है। अब नहीं है।

Shri D. C. Sharma: The goldsmiths and the sarafs are the two eyes....

An hon. Member: Of whom?

Shri D. C. Sharma: Therefore, if we have one eye and not the other, it would not be complete. This distinction between goldsmiths and sarafs should be done away with, and I hope when the rules are framed when the regulations are framed, this will be done.

Mr. Chairman: Shri Karni Singhji.

श्रीमती सहोदराबाई राय : सभापति महोदय, महिलाओं को भी मौका दिया जाये।

Shri Karni Singhji: Mr. Chairman, I rise to support the motion moved by Shri Prakash Vir Shastri to scrap Gold Control and further go on in support of my own amendment, that is, to add at the end of the motion:

> "and adequate compensation be paid to goldsmiths who suffered losses as a result of this measure".

They first bring about legislation that hurts millions of people in this country and then shirk from giving them adequate compensation. It is a matter of very great shame.

This measure was opposed in this House by members of the Opposition when it was introduced. I had myself added my voice of opposition, and at that time we faced a very angry Finance Minister.

Right throughout the country, the Gold Control has been opposed by the millions of our countrymen, not because it affected the rich people of our country but because the masses and the poor people were affected adversely. I do not know how far it is true, but it is said that close to 250 people died in some way or other as a result of this unfortunate measure. As Shri Shastri very rightly said, if this be the case, it is a matter of great shame for any government to bring about legislation which could have resulted in the loss of human life.

The announcement made by the Prime Minister yesterday which brings about certain amendments to the existing Gold Control Act has been hailed by certain section of our people in the country, but I feel that it is an election stunt. If the same thing had been brought in about four months ago or at the time of the AICC session at Bombay, there would have been some grace at least, but now to bring about this small concession at a time when the elections are coming close by proves that whatever grace there could have been also been lost. I only have one fear in my mind, that the Government may reintroduce this immediately after the elections. I hope that that would certainly not be the case.

Shri Nambiar: They do not dare to.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): At least we are thankful for his confidence that we will be returned to power.

Shri Karni Singhji: I do not personally have any doubt that the Congress will be returned to power this time.

An hon. Member: Unfortunately for the country.

Shri Nambiar: Not in States.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य के मुंह मे घी शक्कर।

श्री कर्णी सिंहजी : मैं तो इंडिपेंडेंट हूं।

For any welfare State to some totally ignore the feelings of the people in a democratic set-up is indeed unfortunate. I hope that this Government will now realise that they cannot flout the feelings of the people for any length of time. Legislation brought in without adequate care or planning does no credit to any government. I would only read a portion from the Evidence before the Joint Committee presented to the Lok Sabha. A colleague of mine, Dr. L. M. Singhvi, asked the question:

> "Did the Committee have occasion to form an estimate of the resources required for an adequate and satis-

[Shri Karni Singhji]

> factory rehabilitation of unemployed goldsmiths?"

The reply to this was given by Shri S. S. Khera, Cabinet Secretary:

> "No. We were working purely by rule of thumb. We were limited by the time at our disposal".

That a measure as important as this that could affect millions of people in the country should have been worked out by the rule of thumb is a matter of very great shame and regret to all of us.

Mistakes are made by any administration. This reminds me of what what my father once told me when I was a little boy. He said that the greatest of man will make mistakes but it takes an even greaterman to be able to own up the mistake. I hope that when our Government make mistakes, they will not wait three or four years and let the people of this country suffer before this own up their mistakes but bring in legislation to change bad laws whenever they feel the time is due .

While supporting my amendment for adequate compensation for the goldsmiths, I will go on to say further that Government should not insist on the repayment of loans granted as a rehabilitation measure. Although there is an assurance that those goldsmiths who have been imprisoned will be released, I hope that each and everyone of them will be released, that Government may consider compensation in kind by giving equipment for small home and cottage industries connected with goldsmithy.

Let us bear one thing in mind, that whatever hardships have come to our poor goldsmiths in our country have certainly not been as a result of their fault. It was brought about because our own Government brought in a measure without careful thought, without even realising how adversely the poor man in the street would be affected.

I shall close my remarks by saying only this much that our Government which is so much obsessed with western ideas should realise that all western laws, customs, etc., cannot be imposed on the eastern mind. In our country, for whatever it is worth, gold has a certain intrinsic value for the people. It may be that in America or other countries pure gold cannot be kept by the people, but the same cannot be applied to our country because the yardsticks are different. I believe even Mr. Kamaraj, the President of the Congress Party, has voiced his feelings against gold control, and I am glad that at long last the Government has brought about certain amendments to ameliorate the rigours of this law.

I shall close with just one remark. Let us not in future make the same mistake as we have done this time. You brought in prohibition and you brought in the expenditure tax, now you bring this gold control and scrap it too. The people of India are not here to be experimented with. You have been in power nearly 20 years. I am sure any Government in power 20 years must have learnt a lession or two. I hope no new experiments will be foisted on the people of India so that the Government and the people may have to suffer in the long run as a result of this.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय आज यह जो बहस शुरू हुई है तो मुझे आज की इस बहस में कुछ बात याद आ गई प्रकाशवीर जी के भाषण को सुनने के बाद । माननीय सदस्य प्रकाशवीर शास्त्री जी को बड़ भाई की तरह हम सब समझते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और जो कुछ कहते हैं उस में हमेशा बड़ा बल होता है । पर सब से बड़ी खासियत जो शास्त्री जी की रही है इस संसद् में जिसकी वजह से इतनी मान्यता भी उन्होंने इस ससद् में पायी है, उस का मूल कारण ह उन की मीठी जबान । लेकिन आज वह शास्त्री जी कहां गए जो बहुत मिठास के साथ अपनी बातें संसद में रखा करते हैं । आज तो पता ही नहीं लग रहा था कि वह प्रकाशवीर जी हैं जिनकी जबान के बारे में सारे हिन्दुस्तान में चर्चा है कि इतनी मीठी जबान उनकी है । मुझे तो किसी ने कहा नहीं कि बड़ी मीठी जबान है । लेकिन उन्हें सारा हिन्दुस्तान कहता है कि श्री प्रकाशवीर जी बहुत मीठा बोलते हैं ।

मुझे प्रकाशवीर जी की यह बात सुन कर हिन्दी के एक प्रमुख लेखक श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी की बात याद आ गई। कहानी है "उस ने कहा था"। कहानी शुरू इस तरह होती है गुलेरी जी अपने मुंह से कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इक्के और तांगे वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल जाती है, घाव पक जाता है, उनसे मेरी यह अर्ज है कि वह अमृतसर के बम्बूकार्ट वालों की ज़बान का मरहम लगायें। लखनऊ वह भूल गये थे। तो शास्त्री जी की ज़बान तो मरहम लगाने के लिए हुआ करती है, कोड़े चलाने के लिए नहीं हुआ करती। मैं उनसे यह उम्मीद कर रही थी कि वह आज भी जिस बात को कहेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें सरकार की कोई यह नीयत नहीं थी कि लोगों को तंग किया जाय। जिस बात में अच्छाई है उसे मान कर चलना चाहिए कि उसमें अच्छाई है और उसकी नीयत पर शक करना हमेशा यह बहुत संगत बात नहीं मालूम होती।

दूसरी बात जो मुझे देखने में आई कि हमने जमीदारी मिटायी। जमीदार का नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है। जमीदारी में क्या होता था अध्यक्ष महोदय हमारे यहां भी जमीदारी थी, हमारे घर में भी थी। यही होता था कि रैयत की जमीन, रैयत गोड़ता, जोतता व बोता था, फसल भी काटता था और जमीदार उसका आधा हिस्सा ले लेता था या रेवेन्यू वसूल करता था और कमीशन रख लेता था अपने पास। यही तो जमीदारी में होता था। मुझे वही बात याद आयी। वैसे तो मैं बहुत छोटी हस्ती हूं। परन्तु यह सही बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मने ही नहीं सभी लोगों ने इस बात को बुलन्द किया था कि गोल्ड कंट्रोल कानून जिस ढंग से लगाया गया था जिस नीयत से लगाया गया था चूंकि वह अरमान नहीं पूरे हुए हैं, वह उम्मीदें नहीं पूरी हुई हैं इसलिए इस नियंत्रण को हटा दिया जाय। ..... (व्यवधान) ..... जी हां, नेकनीयती थी, बदनीयती नहीं थी इस के पीछे। यह कहने की मुझे हिम्मत है कि बदनीयती नहीं थी और जिनको बदनीयती दिखाई पड़ती है वह चश्मा हटा कर के नीयती और बदनीयती का फैसला किया करें, यह मैं हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना करती हूं। ..... (व्यवधान) ..... जी हां उसका भी जवाब मैं दूंगी।

तो अध्यक्ष महोदय, जमीदारी का भी यही था। हम इसे भी लाये, अखिल भारतीय कमेटी में कहा गया। सरकार ने वादा किया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा की सरकार ने कहां ह कि इसके ऊपर गौर करेंगे, विचार करेंगे। करनी सिंह जी ने कहा कि उसके बाद समय बहुत गुजर गया। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि संसद् का अधिवेशन जुलाई में शुरू हुआ। मई में यह बात आयी थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने। उसके बाद संसद् का अधिवेशन अभी हुआ। और संसद के अधिवेशन के पहले कुछ हफ्ते तो चले गए विरोधी दल के लोगों कों खुश करने में। दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे वह रोज ले लिया करते थे। उनका हक है पार्लियामेंट पर। हम पर भी थोड़ा हक है। जब तक हम यहां बैठे हुए हैं, उन का हक है हमारे ऊपर और हमारा भी उनके ऊपर हक है। इसीलिए ऐसी बात कहते हैं। तो दो चार घंटे वह रोज ले लेते थे। ज्यादा बातें हो नहीं पायीं। शचीन्द्र चौधरी सहाब ने कहा कि यह जेरे गौर है, हम विचार कर रहे हैं। हम ने एक कमेटी बनाई। मैं इससे सहमत जरूर हूं कि जो गोल्ड कंट्रोल यहां बनाया गया, लागू किया गया, उस में सफ़लता नहीं मिली। परन्तु मैं इससे कतई इकरार नहीं कर सकती कि इसके पीछे नीयत खराब थी। यह ठीक बात है, सोना रखना कोई पाप नहीं है, बुराई नहीं है। बुराई इसलिए हो गई है कि सोना रखना आज हमारे देश के लिये ऐसी ही बात

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

है, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी को अगर यह सुनना पड़े तो पता चलेगा, शायद उन्होंने सुना भी होगा कि आज से पांच साल पहले मैं अमेरिका गई थी तो वहां एक अमरीकी औरत ने मुझ से कहा कि हिन्दुस्तान भी क्या देश है कि खाना नहीं मिलता है खाने के लिए आप दूसरों से मदद मांगते हैं परन्तु जो खाना मिलता है वह सोने की प्लेट में रख कर आप खाना चाहते हैं। यह सही बात है, इस देश में सोने का उपयोग होता रहा है। उस के कई कारण हैं। कुछ सामाजिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं, इसलिए हम लोगों ने यह समझा कि सामाजिक कारण को दूर करने के लिए आर्थिक कारण को दूर करना होगा . . . . .

सभापति महोदय: आप ने कैसे माना कि सोने की प्लेट में खाते हैं?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: : अध्यक्ष महोदय, सब तो नहीं खाते हैं। पर इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि कुछ तो खाते ही थे। यह इसी देश में रिवाज है कि लोगों के घरों में सोने की थालियां और कटोरे मिलते हैं। दूसरे देशों में अजायब-घरों में सोने की थालियां और कटोरे मिलते हैं। यही फर्क है इस देश में और उस देश में। और फिर हम मुकाबिला भी नहीं कर सकते। यही तो कहा गया, इसी बात पर मुझे चोट लगी कि यहां अधिकांश लोगों को खाना नहीं मिलता है, पर यहां यहीं विषम स्थिापित है, यह देश इतना ग़रीब होते हुए भी इतना महंगा सोना खरीदता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन चार मिनट और दें। मैं यह कह रही थी कि वह विडम्बना है, वह एक ऐसी स्थिति है, उसमें कोई शक नहीं कि सामाजिक, सुधार के साथ आर्थिक सुधार करने की जरूरत है। हम ने यह मंजूर किया कि जो नीयत गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट के लागू करने में थी वह पूरी नहीं हुई इसलिए कि यहां गांधी जी नहीं थे। जिस जमाने में हम बच्चे थे, हमारे यहां पर जिस समय गांधी जी ने छूआछूत के खिलाफ आन्दोलन उठाया था उस समय गांधी जी और उन के साथियों ने लाठियां खायी थीं, सिर फूटे थे, कई लोगों की जानें गईं थीं। उन के खून पर यह इतिहास लिखा गया था जिस ने छूआछूत को खत्म किया। कौन सी चीज यह इन्सान नहीं कर सकता? वह इन्सान इन्सान नहीं है जो चाहता हो और कामयाबी हासिल न कर सके। इन्सान के इतिहास में नाकामयाबी नहीं लिखी हुई है अध्यक्ष महोदय, कामयाबी लिखी हुई है। हम जिन्दगी बना सकते हैं। हम मौत नहीं ला सकते। परन्तु यह कहने में मुझे तनिक भी इन्कार नहीं हो सकता कि आज वह गांधी नहीं है इस देश में जो सामाजिक क्रांति के साथ आर्थिक क्रांति चला सकें, राजनीतिक क्रांति चला सकें। इस देश में राजनीकि क्रांति, सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति एक साथ होनी चाहिए। सामाजिक क्रांति नहीं होगी, तो राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती और राजनीतिक क्राति और सामाजिक क्रांति नहीं होगी तो आर्थीक क्रांति नहीं हो सकती। यह तीन कड़ियां हैं जो इकट्ठी रहेंगी। अलग अलग नहीं की जा सकती। इसीलिए गांधी जी चूंकि नहीं थे हमारे देश में, इसलिए हम इस में कामयाब नहीं हो सके। परन्तु इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि गोल्ड कंट्रोल कानून काला कानून था और काली नीयत से लगाया गया था। हमें दर्द नहीं है देश के लिए? आप लोगों को ही सिर्फ दर्द हो गया? मैं मानती हूं कि आप लोगों को भी दर्द है . . . (**व्यवधान**)।

Mr. Chairman: Please conclude now.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: : अच्छा अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करूंगी। एक दो मिनट का वक्त आप मुझे दे दें।

Mr. Chairman: Please resume your seat.

There is very little time at our disposal. The total time was two hours and we have already consumed one hour.

How much time does the hon. Minister want?

16 hrs.

Shri B. R. Bhagat: About 25 minutes.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): What for?.... (*Interruptions*) . . You can speak tomorrow. The reply may be on Monday.

Shri B. R. Bhagat: No, no.

Shri Surendranath Dwivedy: The Chair has always the right to extend the time of the House, if the House agrees. Or, the reply can be on Monday.

Shri B. R. Bhagat: That distorts the picture. Let the whole debate be over today; I do not mind sitting late.

Mr. Chairman: Hon. Members should take not more than five minutes. The hon. Member may conclude now.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभापति महोदय, मैं ने कुछ लम्बा समय ले लिया इसलिये कि मुझे अपने विरोधी दल के भाइयों से बात करने का मौका नहीं मिला था अब तक। अब मैं अपने सुझावों पर आती हूं जिस में एक मिनट लगेगा।

एक माननीय सदस्य : आप शेर जरूर कहियेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जरूर कहूंगी। पहले तो मुझे यह कहना है कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह बहुत ही सही कदम है क्योंकि 14 कैरट का कानून चल नहीं सका। दूसरा कदम जो उठाया है रिफाइनरीज को कंट्रोल करने का यह भी सही कदम है। आज उस को आप अपने कंट्रोल में रखिये, लेकिन जहां तक गोल्ड का सवाल है वह स्टेट के अधिकार में होना चाहिये क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां पर गोल्ड का व्यापार प्राइवेट सैक्टर में होता है। अमरीका में भी जो कि एक पूंजीवादी देश है, गोल्ड का व्यापार प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। गोल्ड रिफाइनरीज की जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिये।

मैं सरकार से एक यह अपील भी करना चाहती हूं कि सरकार खुद कहती है कि 40 करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज देश में स्मगल होता है। सरकार खुद 40 करोड़ रुपये का सोना इम्पोर्ट करे और उस को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा इस देश में सुनारों को बेचे। वह जो गहने बनायें उस में से एक तिहाई या एक चौथाई को उन को बाहर बेचने का अधिकार दे। अगर यह इन्तजाम सरकार कर दे तो इस से लोगों को बड़ा फायदा होगा।

बैठने के पहले मैं एक अर्ज और करना चाहती हूं। जब कोई कभी अच्छी बात करे या कहे तो उस के लिए कभी कभी दाद भी दी जानी चाहिये। इस के सम्बन्ध में मुझे गालिब का यह शेर याद आ रहा है :

"यह कहां की दोस्ती है, बने हैं दोस्त नासेह,
कोई चारासाज होता, कोई गमख्वार होता।"

श्री बिशनचन्द्र सेठ : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मेरा यह बिजिनेस है, ऐसा न हो जाये कि समय खत्म हो जाये और मुझे बोलने का अवसर न मिले।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): I am very glad that the Prime Minister has made a statement yesterday, though it is not to the extent that some people would have liked it, some people who wanted that gold control should be completely ruled out. That would have been a proper step. I do not want to say anything in a spirit of humiliating the Government. I want to say that they have taken this step and they will soon find that the step they have taken is half-hearted and they would have to take proper, further steps very soon.

Secondly, I want the people also to consider this. In India we pay Rs. 140 or Rs. 150 per tola of gold while in other countries people pay only Rs. 70 or 75. What is this odd fascination in the minds of the Indian people for gold? Is it the idea of the Indian people to see that their women are ornamented in gold every day? This

[Dr. M. S. Aney]

fundamental attitude of mind must be changed; if we want to really have what they call a social welfare State, I have no doubt that they would have to change this view, and the fascination which they have for gold should be abandoned. They must take a realistic view. The world robs you every day. They purchase gold at Rs. 70 and sell it to you at Rs. 140; every day we allow ourselves to be robbed like that. Thousands of people were out of work and they were brought back to employment. That is a good thing, but there should be this distinction. I feel that this should be an occasion for us to seriously examine for ourselves whether the attitude of the Indian people to gold which exist today should be maintained. Will it help you to keep up the solvency of the country or will it be making us insolvent one day? That is the point which I wanted to put before the House for consideration. I think the idea that I have put forward will be seriously considered by the House.

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह) : सभापति महोदय आप ने मुझे बोलने का मौका दिया इस के लिये मैं आप की आभारी हूं। जब गोल्ड कंट्रोल आया था उस समय श्री मोरारजी देसाई यहां पर वित्त मंत्री थे। उस समय भी मुझे बोलने का मौका मिला था। मैं ने उन से यह प्रार्थना की थी कि जब वह इस तरह का बिल लाये हैं तो कोई ऐसी धारा जरूर उस में जोड़ी जाये जिस में कि देहात में रहने वाली जो अधिकांश जनता है, जो किसान हैं, उन को जरूर राहत मिले। लेकिन देहात के अन्दर रहने वाली जनता के साथ पिछले तीन सालों में बड़ी गड़बड़ी हुई है। गोल्ड कंट्रोल से उन को कोई फायदा नहीं हुआ उस से लाखों आदमी लखपति बन गये और लाखों मिट्टी में मिल गये। जो बड़े बड़े सुनार थे वह लखपति हो गये और जो छोटे सुनार थे वह मिट गये। जिन सुनारों का पहले भी बोलबाला था उन्होंने करोड़ों रुपये बना लिये लेकिन गरीब सुनार परेशान हो गया। वह लोग आज मारे मारे फिरते हैं। उन को गोल्ड कंट्रोल से कोई धन्धा नहीं मिला कोई रुपया नहीं मिला कोई राहत नहीं मिली जो कुछ हमारी बहन ने अभी कहा वह बिल्कुल ठीक कहा है लेकिन इस में कोई धारा ऐसी अवश्य जोड़ी जानी चाहिये जिस से हमारे देहातों की जनता को, किसानों को, राहत मिले।

पहले हमारे देश में जेवर इस लिये बनाये जाते थे जिस में कि हमारी सन्तान की उससे सहायता मिले, उस समय जेवर इस लिये बनाये जाते थे कि अगर कभी घर में पैसा कम हो तो उस का उपयोग इस के लिये किया जाये। उस का उपयोग शादियों में, लेन देन में, काश्तकार की लगान वसूली में, तकावी आदि में होता था। हमारे लोग जेवर को इस लिये पसन्द करते थे कि अगर घर में जरूरत पड़ती थी तो उस का दूसरों से कर्ज लेने में उपयोग हो सकता था लेकिन उस समय हमारे वहां सोने का गलत लाभ भी उठाया गया। जब हम दूसरों से ऋण वगैरह लेने जाते थे तो हमारे जेवर आधे दामों में ले लिया जाता था और हम अपने विकास के लिये उस का उपयोग नहीं कर पाते थे जिस से किसानों को बड़ा नुक्सान हुआ।

लेकिन इतना सब होते हुए भी जो गोल्ड कंट्रोल किया गया उस से हमारे बहुत से सुनार बेघर हो कर मारे मारे फिरते हैं। इस लिये में प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस ओर हम विचार करें और यह भी सोचें कि आज कांग्रेस मेम्बर चाहे जो कुछ बोलें लेकिन हमारे विरोधी भाई इस चीज का फ़ायदा उठा ले जाते हैं। इस प्रकार की बहसों के बाद वह कहते हैं कि हम ने इस कानून को ठीक करवाया है कांग्रेस वालों ने नहीं करवाया। मैं सरकार के इस निर्णय का समर्थन करती हूं और कहती हूं कि ऐसा कदम उठाया जाये जिस से स्वर्णकारों को भी राहत मिले और देश को भी राहत मिले।

लेकिन यहां का तस्कर व्यापार जो चल रहा है उस को रोकने की बड़ी आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारी बाउंड्री पर से तस्कर व्यापारी सोना ले आते हैं और

यहां पर ला कर उस को जयपुर में बेचते हैं अहमदाबाद में बेचते हैं, बम्बई में बेचते हैं, लेकिन आप को उस का पता नही लग पाता है। हमारे लोग भूखों मर रहे हैं और इस गरीब देश का लाखों करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो रहा है। आप को चाहिये कि आप अपनी सी०आई०डी० को इस के देखने का काम सौंपिये जिस में सोने का तस्कर व्यापार बन्द हो और हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। हमारी बहन ने कहा है कि शास्त्री जी की बोली बड़ी मीठी है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी बहन की बोली शास्त्री जी की बोली से भी मीठी है। महिलाओं को स्वयं अपने लिए सोने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको अपनी संतान के लिए सोना चाहिये होता है उसके लिए आवश्यकता होती है। वक्त जरूरत चूंकि सोना काम आ जाता है इस वास्ते वे ज़ेवर बना कर अपने पास रखती हैं। परन्तु जब देश को सोने की आवश्यकता होती है तो देश को सोना देने के लिए भी वे हमेशा तैयार रहती हैं। अभी पिछले दिनों चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। हमारी सरकार को सोने की जरूरत पड़ी थी। हमारी महिलाओं ने तब सोना दिया था, पुरुषों ने नहीं दिया था, महिलाओं ने दिया था। उन्होंने देश की रक्षा की खातिर अपनी चूड़ियां, मंगल सूत्र आदि तक दे दिया। भारतवर्ष की महिलाओं ने हर कोने से पैसा दिया। पुरुषों ने नहीं दिया। पुरुष लोभी होते हैं, लालची होते हैं।

इस गोल्ड कंट्रोल की वजह से लाखों मन सोना बड़ बड़े व्यापारियों ने बड़े बड़े सर्राफों ने गाड़ कर रख दिया था। अब वह सब बाहर निकल आएगा। मैं सुनारों से अपील करना चाहती हूं कि आज संकट का समय है और वे ज्यादा आन्दोलन न करें। उनको रियायतें मिल गई हैं और जो वे चाहते थे वह उनको मिल गया है। मैं गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करना चाहती हूं कि जितनी महिलाओं को तथा जितने सुनारों को उसने गिरफ्तार किया है, जितने अनशन करने वालों को उसने पकड़ा है उन सब को उसे तुरन्त छोड़ देना चाहिये। स्वस्थ वातावरण का हमें आज देश में निर्माण करना है। आज जरूरत इस बात की है कि कंधे से कंधा मिला कर हम सब आगे बढ़ें मिलजुल कर आगे बढ़ें। अगर कोई यह कहता है कि कांग्रस हार जाएगी तो मैं उनको कहना चाहती हूं कांग्रेस सैंट परसेंट बहुमत में आएगी। विरोधी दल वाले चाहे जितना आन्दोलन करें वे कुछ नहीं कर सकते हैं, उन से कुछ नहीं हो सकेगा। जनत जानती है कि कांग्रेस के सिवा इस देश का कोई शासन चला नहीं सकता है। विरोधी दल वाले चाहें भी तो उन से शासन चलने वाला नहीं है। उन में कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो शासन सूत्र को सम्भाले रख सके।

हमारे भाई खूब हल्ला करते हैं। मैं उन से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वे हल्ला न किया करें। आज संकट का समय है। उनको चाहिए कि संसद् के काम को अच्छी तरह से चलने दें। ज्यादा ऊधम न मचायें। ऐसे काम किये जाने चाहियें जिन से देश आगे बढ़े, देश तरक्की करें और आप और हम दोनों बैठे रह सकें और कोई गड़बड़ी न हो। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह सुनारों को जल्दी से छोड़ दे। मेरे पास महिलायें रात दिन आती हैं और कहती हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। वे रोती फिरती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि ऐसा न हो कि किसी की डैथ हो जाए, जो अनशन करने वाले हैं उन में से किसी की डैथ हो जाए। इस वास्ते उनको जल्दी छोड़ दिया जाना चाहिये और ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिये जिस में जनता को सुविधा हो।

Mr. Chairman: Shrimati Vimla Devi. Only five minutes each.

Shrimati Vimla Devi: I would request you to give 10 minutes for women Members. *(Interruption)*.

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Minister will start his speech at 4.45, and I have requested him to complete his speech

[Mr. Chairman]

within 15 minutes. I will try to accommodate as many Members as possible. After all, many things need not be said: I request hon. Members to conclude within five minutes.

Shrimati Vimla Devi: Mr. Chairman, Sir, without going into all the aspects of gold control, the Government suddenly in 1963 promulgated the Gold Control Order with the object of stopping smuggling, to bring out the concealed gold, reduce the price of gold, wean the people away from the love of gold and to make the people invest in the economic developmental plans. But none of these five objectives has been achieved.

The Government wanted to stop smuggling; but smuggling is on the increase after the Gold Control Order came into being. The Government have confiscated only five per cent of the smuggled gold whereas Rs. 40 crores to Rs. 50 crores worth of gold is being smuggled into this country. One-fourth of it is going into the making of ornaments and three-fourths is being hoarded. Instead of chasing the hoarders of gold, the Government always choose the small people and the goldsmiths who are using just one-fourth of the quantity. They are very much afraid of going and searching the houses of big people. When one or two houses of big people were being searched, the Finance Minister immediately interfered and then he was apologising, rather, he was seeking the apology from the Enforcement Directorate who went to check these houses. To the appeal of the goldsmiths and the smaller people the Government was deal. They always wanted the Opposition to give concrete suggestions, but they have not followed even one concrete suggestion out of the suggestions given by the Opposition. When the Gold Control Order was promulgated, we said that smuggling would not be stopped unless the bullion market was brought under Government control. But they did not want to do it. They said that the Government cannot buy because they cannot lose foreign exchange. Anyhow, Rs. 58 crores worth of foreign exchange was lost. So, I am glad that at least now they are considering the bringing of the bullion market under their control.

Then, let me refer to the investment of gold by the common people in our development schemes. The common people are afraid of investing in banks because, after the experience of the Palai Bank, they are afraid of investing in private banks and also because they do not believe in Mundhras and Jains. What about the Government? They do not want to invest in the Government schemes because after collecting the poor tax-payers' money, the Government are investing it only on Dharma Tejas who swindle the Government's money and through the Government they swindle the people's money. So, before the Government asks the people to invest in these schemes, it must win the confidence of the people to make them invest in the schemes.

What about women? Men always say—at least not all but a few Congressmen always say—that women are very much in love with gold, much more than their husbands; that they want to hoard gold; and they say, why not give up gold. Let the Government give the women or the girls security, education, employment and a right in their fathers' property. If this is done, the women will give their gold to the State.

श्रीमती सहोदराबाई राय . महिलाओं को सोने से प्यार नहीं है । वे तो सोना अपनी संतान के लिए रखती हैं, उसके लिए बनवाती हैं ।

Shrimati Vimla Devi: Since I do not have much time....

Mr. Chairman: A minute more.

Shrimati Vimla Devi: .... I shall confine my remarks to a few points. I want the Government to scrap the Gold Control Order completely. I shall proceed with the subject point by point. I do not agree with Shri Masani when he said that the bullion market cannot be, controlled by Government. Surely, they can afford to buy gold at the international market rate and supply the people To some extent—I do not say totally—smuggling could be stopped that way. The bullion market must be brought under Government Control.

If the Government are going to follow the concrete suggestions from us, then I will give one suggestion. I want a ceiling

to be put; the middle-class people must be able to confine themselves to a ceiling. I do not want any hoarding in the form of ornaments also. Hoarding in ornaments is also bad. I want the ceiling to be within the reach of the middle-class people.

I do not congratulate the Government on having given the concession, as was said by the Prime Minister. I congratulate, on the other hand, the valiant people, the goldsmiths and others who fought for three years and suffered for this cause. They were on the path of agitation, and because of that agitation, and because they had the full backing of the middle-class people and others, they were able to win this concession from the Government. I am convinced that any amount of question or solution of problems raised in the House by the Members are not acceptable to the Government, but that when there is a big mass agitation of the people, only then the Government are driven to come forward with their proposal. I congratulate the goldsmiths and others, for their success.

Lastly, I want that all the goldsmiths who have been in jail should be released. Suicide cases have been launched against many of them, but who is going to launch cases against the murderers of three hundred goldsmiths? I want those cases to be brought before an eminent judge for enquiry. Finally, I want that the loans which have been given to the goldsmiths should not be cut down.

श्री कमलनयन बजाज : सभापति जी, स्वर्ण नियंत्रण नियम इस सदन में जब पेश हुआ था तो मैंने काफी नम्रता, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया था और यह आशंका जाहिर की थी कि इस नियम को बनाने से देश को कोई लाभ नहीं होगा, और इसमें कोई सफलता प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं है। उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनका रोष भी मुझ को सहना पड़ा था। मुझे दुख एक ही बात का है। भगवान से मैंने प्रार्थना की थी इस सदन में कि मैं लाख बार गलत निकलूं, जो मेरी राय है वह लाख बार गलत निकले और सरकार लाख बार सही निकले, पर भगवान ने मुझ को ही सही निकाला और हमारी सरकार गलत निकली, इसका मुझे हृदय से दुख है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या माननीय सदस्य ने इस के समर्थन में वोट नहीं दिया था ?

श्री कमलनयन बजाज : माननीय सदस्य जानते हैं कि वह अपने पक्ष के लिये क्या करते हैं। हम भी अपने पक्ष के नियमों के विरुद्ध नहीं जाते हैं, लेकिन हम ने जो सलाह देनी होती है वह हम स्पष्ट रूप से दे देते हैं। पार्टी से खेल करने के लिये हिम्मत की दरकार नहीं है। हम जो बात कहते हैं, साफ साफ कहते हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने गोल्ड पर से चौदह कैरट का प्रतिबंध हटा दिया है और अब सोने के गहने अच्छे सोने के बनाये जा सकते हैं। लेकिन इस से हमारा कार्य सफलता से पूरा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जब गोल्ड का नियंत्रण लाया गया, तो सरकार के सामने दो प्रश्न थ, एक तो गोल्ड स्मगल हो कर देश में आता था और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपये की कीमत गिरती जा रही थी। जिस तरह से गोल्ड रूल्ज को माडिफाई किया गया है, उस से इन दोनों प्रश्नों को हल करने में किसी तरह से मदद नहीं मिल सकेगी जब तक भारत में सोने का भाव सोने के अन्तर्राष्ट्रीय भाव से दुगने से अधिक है, तब तक सरकार कितने भी नियम बनाये स्मगलिंग को रोकना हमारे और सरकार के बूते के बाहर की बात है।

इस के लिये सब से अच्छा तरीका यह है कि जब जनता चाहती है कि उस को स्वर्ण मिले, तो हमारे पास

[श्री कमलनयन बजाज]

विदेशी मुद्रा की कमी होने के बावजूद सरकार को 100 करोड़ रुपये का सोना विदेशों से ला कर देश में देना चाहिये। उससे विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ती होगी आज यदि हमारे किसान के पास क्राप अच्छी हुई, तो वह उस को वेच कर न जमीन ले सकता है, न स्वर्ण ले सकता है और न ही कोई दूसरी चीज ले कर अपनी बहन, बेटी या स्त्री को दे सकता है। यदि हम उस को सोना दे सकेंगें तो वह कम से कम अनाज वेचने के लिये बाजार में ले आयेगा । इस प्रकार जितना अनाज बाजार में आयेगा, उतना अनाज हम को विदेशों से कम लाना पड़ेगा। इस के अतिरिक्त इस समय हम शिपिंग फ्रेट पर जो 125 करोड़ रुपये दे रहे हैं, उस में भी हम काफी बचत कर सकेंगे। मेरा तात्पर्य यह है कि यह कदम उठाने से हम देश में सोने की कमी को पूर्ती करेंगे, लोगों को सोने की चाह की पूर्ती करेंगे और इस के साथ ही हम देश की दरिद्रता में कमी करेंगें।

श्री शशिरंजन (पपरी) : आज साधारण किसान के पास अ ज कहां है ?

श्री कमलनयन बजाज : आज जो पांच सात परसेंट की कमी है और कल्टीवेटर जो अनाज बाहर नहीं ला रहा है, उस के कई कारण है। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं उसके बारे में भी बता सकता हूं।

माननीय सदस्या, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि अमरीका में रिफाइनरीज का काम सरकार के अधीन होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरीका में आम जनता सोना खरीदती नहीं है। वहां पर लोगों को आराम और लक्सरी की लाखों चीजें मिलती है, जिस की वजह से उन को सोने की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस देश में हजारों लाखों, करोड़ों लोग कम या ज्यादा परिमाण में सोना खरीदते हैं, वहां पर अगर रिफाइनरीज पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण कर दिया जाये, तो देहात में जो चौदह कैरट के गहने बनाए गये है, अगर कोई उन को बाइस या चौबिस केरट का बनवाना चाहेगा, तो उस सोने को रिफाइन करने के लिये कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास आदि भेजना पड़ेगा। इस में व्यवस्था का बड़ा कठिन सवाल पैदा होगा और इस से लोगों को भी बड़ी तकलीफ होगी।

जब इस सदन में डीवैल्युएशन पर चर्चा हो रही थी, उस समय हमारे भूतपूर्व सुरक्षा मंत्री जी ने एक बात कही कि डालर को डीवैल्यु कर दिया जाये, तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ़ से तालियां बजाई गईं। मुझे यह बात सुन कर ताज्जुब हुआ और इस सम्बन्ध में कैट और माउस की कहानी याद आई। सवाल यह है कि अगर डालर को डीवैल्य करना है, तो घंटी कौन बांधेगा। If Mohammed does not go to mountain, mountain should go to Mohammed.

अगर डालर को डीवैल्यु करना है, तो अपने रुपये को हमें रीवल्यु और ओवर-वैल्यु करना होगा। अगर हम अपने रुपये को रीवैल्यु और ओवर-वैल्यु करते हैं, तो न सिर्फ़ डालर, बल्कि सारी की सारी विदेशी करेन्सी हमारी करेन्सी की तुलना में डीवैल्यु हो जाती है।

अगर हम अपने देश में ज्यादा सोना ला कर रखेंगे, तो विपत्ति के समय वह सोना हमारी सुरक्षा के लिए भी काम देगा। आज देश में सोने पर नियंत्रण रखना हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी बात नहीं है। हम देश में सोना वाजिबी तौर से ला कर बेचें,

यह सब तरह से देश के हक़ में है । यह मेरी आख़िरी विनती है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सभापति महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड कंट्रोल के सम्बन्ध में जो इन्फ़ार्मल कमेटी बनाई, उसमें उसने ऐसे आदमियों को रखा, जिनको पार्लियामेंट ने नहीं चुना था और जो ऐसे पूर्वाग्रह के आदमी थे कि गवर्नमेंट को भी यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह उनकी बात को नहीं मानती है और वह गोल्डस्मिथ्स को 22 कैरट प्यूरिटी का सोना प्रयुक्त करने देगी । चूंकि सुनार लोग यहां पर अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत दिनों से तकलीफ़ उठा रहे थे—कल हम ने यह नज़ारा देखा कि लाखों की तादाद में वे गोल्ड कंट्रोल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे—इसलिए गवर्नमेंट ने उनको कुछ शान्ति देने के लिए यह कार्यवाही की है ।

लेकिन सवाल यह है कि यह कार्यवाही शुभ नीयत से की गई है या बदनीयती से की गई है । गवर्नमेंट ने एक तरफ़ तो यह कह दिया कि 22 कैरट प्यूरिटी के ज़ेवर बनाये जा सकते हैं, लेकिन साथ यह भी कह दिया कि लोगों ने जो सोना डिक्लेयर किया हुआ है, वह हमारे पास लाया जाये, हम सारा सोना ले लेंगे और लोगों के पास सोना नहीं रहने देंगे ।

श्री ब० रा० भगत : गवर्नमेंट नहीं लेगी । लोग उसके ज़ेवर बनवा सकते हैं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : ज़ेवर बनवाने के लिए पैसे कहां से आयेंगे ? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार लोगों का सोना ले लेगी और उसको हज़्म कर जायेगी और वह इस बारे में बदनीयती से काम ले रही है ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : माननीय सदस्य नीयत का मामला न उठायें—अक्लमंदी और बेवकूफी का उठायें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी तो यह है कि दुनिया तो कहती है कि किसी चीज़ में मिलावट न हो, लेकिन इस बेवकूफ़ गवर्नमेंट ने यह कानून बनाया कि मिलावट करो और बेचो । दुनिया भर में एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए कानून बनाये जाते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने एडल्ट्रेशन करवाने के लिए कानून बनाया ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह एडल्ट्रटिड गवर्नमेंट है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस एडल्ट्रेटिड गवर्नमेंट ने एडल्ट्रेटिड ला बनाया है ।

श्री कमलनयन बजाज जैसे दोस्त कहते हैं कि जब यह कानून बनाया गया था, तो उन्होंने उसका विरोध किया था । एक माननीय सदस्या ने कहा कि वह इसके पक्ष में भी थीं और विपक्ष में भी थीं । इस समय सब तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उस ने गोल्ड कंट्रोल लागू किये जाने के वक्त राय क्या दी थी । इन लोगों ने राय तो यह दी थी कि गोल्ड कंट्रोल किया जाये । राय एक देने और ज़ुबान से दूसरी बात कहने से मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है ? वह जो कुछ अब कहते हैं, अगर उन्होंने वही किया होता, तब तो उन की बात समझ में आ सकती थी ।

पाकिस्तान से आने वाले रेफ़्यूजीज़ को जो लोन दिये गये थे, सरकार ने उन लोन्ज़ को वाइप आउट करने का कानून बनाया था । मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह वाकई गोल्डस्मिथ्स को रीहैबिलिटैट करना चाहती है और वास्तव में चाहती है कि 22 कैरट प्यूरिटी के ज़ेवर बनाये जायें, तो

[श्री कमलनयन बजाज]

गवर्नमेंट की तरफ़ से गोल्डस्मिथ्स को जो लोन दिये गये थे, तरस तरस कर उन्होंने जो लोन लिये थे, गवर्नमेंट उन लोन्ज़ को वापस लेने के लिए कोई कदम न उठाये। गवर्नमेंट के लिए यह मौका है कि वह स्वर्णकारों के प्रति अपनी सहानुभूति और शभ नीयत का परिचय दे सकती है। अगर वह यह कदम उठायेगी, तो लोग समझेंगे कि उसने वाकई गोल्डस्मिथ्स के फ़ायदे के लिए कुछ किया है।

दूसरे मैं यह कहता हूं कि जब आप के मुंह से यह बात निकल गई कि हम 22 कैरेट गोल्ड को मानते हैं और इंटेरिम रिपोर्ट जो कमेटी की है उसको नहीं मानते हैं, तब जिन लोगों को आप ने जेल में रखा है उनको फौरन रिहा कर देना चाहिये। उन आदमियों को जेल में रखने का आप को कोई अधिकार नहीं है।

मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट सचमुच शुद्ध नियत से इस में जा रही है तो साथ में यह भी होना चाहिये कि जितने भी हमारे सुनार हैं और जो सुनार इस धन्धे को करना चाहते हैं उन को एक रुपये का सर्टिफिकेट दे कर इस धन्धे को उन से न कराये। उनका जो धन्धा उनके बाप दादे के समय से चला आ रहा है उसको चलाने के वास्ते उनको पूरी सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अमल में आने से पहले भी आप ने जो कस्टम्स ऐक्ट बना रखा है उसके मातहत छापे मार कर आप लोगों को पकड़ते हैं और उन पर मुकदमा चलाते हैं, लेकिन एक दिन आप उनको पकड़ते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं इसमें जो बेईमानी चलती है उसको रोकने के लिये आप को आंखें खोल कर रखनी पड़ेंगी और हमारी बात सुन कर अपने कार्यों से हम को प्रतीति करानी पड़ेगी कि आप की नियत साफ है।

Some hon. Members *rose—*

Mr. Chairman: Shri Hanumanthaiya—

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Sir, I had also given my name . . .

Shri K. C. Sharma: My name was also there....

श्रीमती कमला चौधरी (हापुड़) मैं ने भी अपना नाम दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं ने अमेंडमेंट मूव किया है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह दर्ख्वास्त करूं कि आप के सामने भाषण हो रहे हैं। समय जितना हमारे पास है, आप जानते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकेगा कि एक के बजाय दो या तीन लोगों को एक साथ सुनूं। जितना समय है मैं कोशिश करूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बुलाया जाये।

एक माननीय सदस्य : मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि समय बढ़ाया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : जिन लोगों ने अमेंडमेंट मूव किये हैं उनको तो जरूर मौका दिया जाना चाहिये।

Mr. Chairman: According to the time that is allotted to this item, I am supposed to call the hon. Minister at 4.45 which will give him just about 12 minutes.

Shri S. M. Banerjee: Let him reply on Monday.

Shri B. R. Bhagat: No, no. Let us sit and finish it.

Mr. Chairman: I am absolutely in the hands of the House. Whatever the House asks me to do I will do.

श्री शिव नारायण (बांसी) : इसका समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : तब फिर मेरा सुझाव है कि हाउस के सामने श्री शिव नारायण यह

प्रस्ताव रखें कि इस का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये ।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): Sir, there are two Half-hour discussions put down for today. They also refer to some very important subjects. If this discussion is extended by an hour, it will go up to 6.00 and then the two Half-hour discussions will be pushed out. That is very undesirable......

Mr. Chairman: I have not been able to follow.

Shri Surendranath Dwivedy: He is saying that there are two Half-hour discussions and if the time for this is extended by one hour they will not be taken up today.

An hon. Member: You should extend the time of the House by one hour more today.

Mr. Chairman: Let me hear Shri Mukerjee.

Shri H. N. Mukerjee: My suggestion is that if the House wishes to extend the discussion on the Gold Control Order, it may well be continued on Monday, because if today the extension is given then the likelihood is that the two Half-hour discussions would be pushed out. It would be, I submit, a most undesirable procedure.

Mr. Chairman: That can only be possible if the time is extended.

Shri S. M. Banerjee: If the hon. Minister does not want to extend the time, I have only one suggestion. Let this continue till 5.00, let the two Half-hour discussions be taken up, and let the Minister take 15 or 20 minutes on Monday.

Mr. Chairman: In order to accommodate as many hon. Members as possible, I agree that the hon. Minister will reply on Monday.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्रस्ताव का जो अभिप्राय है सोना नियन्त्रण के प्रश्न को ले कर उसको सरकार ने प्राय: स्वीकार कर लिया है । जहां तक स्वर्णकारों

को सहायता पहुंचाने की बात है, सहयोग की बात है, क्वालिटी कंट्रोल हटा दिया गया है और स्वर्णकारों को उससे सन्तोष हो गया है । ऐसी स्थिति में परसों उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये । उत्तर आज ही होना चाहिये और इस प्रश्न को आज ही समाप्त करना चाहिये । एक सस्पेन्स पैदा करने की आवश्यकता नहीं है । इसका उत्तर आज ही होना चाहिये और इस प्रकरण को आज ही समाप्त कर देना चाहिये ।

Shri Muthyal Rao (Mabbubnagar): Sir, we have got some other difficulty. So, as decided by the Speaker, the Minister will have to reply today. So, I would beg of you to reconsider your decision.

श्री ब० रा० भगत : इसको अगले दिन के लिये न रखिये । आप चाहें तो मुझे सिर्फ पन्द्रह मिनट दे दें ।

श्री कमलनयन बजाज : आप एक बात का खयाल रखिये कि यहां कितने स्वर्णकार बाहर से आये हैं वे यह जान लेना चाहते हैं कि सरकार का क्या उत्तर है ।

Mr. Chairman: I would suggest one alternative. We will continue discussing this problem up to 5.15 p.m. Then, we will take up the half an hour discussion. Now, Shri Hanumanthaiya.

Shri Hanumanthaiya (Bangalore City): Yesterday, the statement made by the Prime Minister on gold control has brought almost universal satisfaction. The Gold Control Order met with great opposition when it was made. Many of us, even in the Congress Party, felt that this measure may work hardship, may result in waste of money, may not be able to succeed in achieving its objective. Yet, in spite of our better sense, we allowed this Order to be promulgated and worked. Subsequent events showed that we were justified in our apprehension that the Gold Control Order was doing more harm than good.

In the month of April, during the last session of Parliament, I had the opportunity

[Shri Hanumanthaiya]

to propose the scrapping of the Gold Control Order on the floor of this House. I quoted even the author of the measure, Shri Morarji Desai, to show that he was also in favour of scrapping the Gold Control Order, because he was not satisfied with the way in which it was being implemented. Whatever may be the reason, he was of that opinion. Members from all the sides of the House, whether it was the Communist Party, Swatantra Party, Congress Party or the PSP, and the Members of the other House were of the view that it was time that we revised the Gold Control Order so as to see that its harmful effects are done away with.

But, Government took a long time. They appointed a Committee. It is a revealing thing that when a Committee of officials was appointed, it did not see what the public feeling was, what the public demand was. It saw from its ivory tower what was, in its opinion, good for the country or for the economy. We often say that in a democracy the people are sovereign. Having said that, we behave like sovereigns ourselves. Here is an instance where public opinion has expressed itself and yet those people who are in the ivory tower, went against it.

The Gold Control Order has got both good and bad aspects. So far as hoarding gold is concerned, it is necessary that this Order should remain. Here I have got to make a suggestion. Very few of us have understood the place of gold vis-a-vis currency. In the international monetary world, people are thinking of reform. France, in particular, is advocating the return of currency to the gold standard. I am not prepared to say that is a desirable thing, but I am only pointing out that people have begun to think, very great people, people who have got experience, people who are experts in the line, have begun to think in terms of restoring the gold standard.

About ten advanced countries of the world are also engaged in the discussion as to what form of international currency is necessary to meet the demands of the time. What I am pleading is that we have to think afresh on the problem of gold, its place in our economy in relationship to the currency. If you leave it to permanent officials, they will not be able to see what is happening beyond their files or probably beyond their air-conditioned rooms. This is a matter where a person has to keep his eyes and ears wide open not only to what is happening in this country, either in the villages or in the towns, but in the world.

I, therefore, earnestly suggest to Government that a committee must be constituted of the concerned people to examine the problem of gold afresh. This is being done in the world. This is being done by all thoughtful people in the world. We wake up too late to solve this all-important problem which either makes our currency value more or less we will not be able to take a decision in time, unless we make a thorough study in advance.

This revision of the Gold Control Order should have been done earlier. The opinion of Members of Parliament was disregarded: the opinion in the country was disregarded. So much suffering was occasioned. They only wanted to consult a few officials and they did consult them. The advice that was given was not, as everyone knows, conducive to democratic or set-up. This baby, the Gold Control Order, nobody was prepared to hold. The Finance Minister also was not prepared to hold it. Ultimately, it is the Prime Minister who summoned courage enough to handle it and handle it effectively. I am, therefore, specially thankful to the Prime Minister that she handled this issue wisely and in a way that is acceptable to the people.

One suggestion I shall make and close my speech. So far as all those people who have been arrested in connection with the agitation against the Gold Control Order are concerned, they in a way stand justified. Therefore let them be released immediately and let a happy atmosphere be restored in the country.

Shri A. K. Gopalan: Mr. Chairman, the announcement of the Prime Minister yesterday in the House to modify the Gold Control Order will no doubt give some relief to the goldsmiths and the gold workers. The demonstration of the goldsmiths in

front of Parliament has been withdrawn and I will request that those who were arrested should be released immediately and the cases against those people should be withdrawn.

I would have felt grateful if these steps had been taken three years age. The Government after cruel harassment of the poor goldsmiths for more than three years after reducing the families of thousands of goldsmiths into destitutes, leading to suicides of hundreds of goldsmiths, after beating to pulp a large number of goldsmiths, firing and teargassing them and after putting thousands of gold workers into prisons—after all this—is coming forward with this modification.

16.44 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The plight of the goldsmiths during the last three years can be compared only with the plight of Indian artisans who were turned into destitutes under the regime of the British East India Company.

While modifying the Act the Government also proposes to maintain certain provisions to continue the harassment of the goldsmiths. Therefore the concessions are only partial and will not satisfy them to the fullest extent. These half-hearted measures will not solve the basic problem. I want to state that I am for mobilising hidden gold for the cause of the country; I am for putting an end to the smuggling of gold, but these noble aims, which are supposed to be the purpose of the Gold Control Act, are sought to be defeated due to the policy of the Government. The gold-smugglers have been carrying on their activity merrily despite the penalties provided by the Act. The Customs officials continue to play an important role abetting this crime and the Gold Control Act has not obstructed the anti-social practices. Government knows very well how gold is being smuggled into this country. Exporters deliberately under in voice their products while exporting their products and illegally obtain a higher amount through their agencies abroad. This illegally acquired foreign exchange is brought in the country in the form of gold through smuggling. Since the price of gold is much higher in India than the prevailing international prices, these smugglers get a higher return for their transactions. This is going on since long and the Government is fully aware of it. But the Government has not been able to stop this smuggling.

The other day, it was pointed out in the House that there is a big gap between the value of exports and the amount of foreign exchange earned. The businessmen responsible for this either deposit the part of the foreign exchange earned in foreign banks or smuggle it in the country in gold chips. The much advertised raids organised by the Customs officials are often resorted to compel the gold smugglers to pay more bribe. Though Walcot has been arrested, there are many more such Walcots who are enjoying official patronage today.

As far as the production of gold is concerned, I want to point out that in 1961-62, India produced 1,36,498 ounces of gold while in 1966-67, the production is estimated at 1,10,000 ounces.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri A. K. Gopalan: I want to point out that the question of all the questions is whether the Government is serious to put an end to the smuggling of gold by nationalising all the export and import trade and whether it is keen to unearth all the stocks of hidden gold. The operation of the Gold Control Order during the last three years is a convincing proof that there is not an iota of concern in the approach of the Government to these important issues. So, if the Government does not want to change its bullion policy drastically and punish severely the gold hoarders and smugglers, then it is better that the Act be scrapped.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार ने अपने जीवन-काल में मुख्य रूप से चार 'बन्दिया' की हैं और वे चारों ही पूरी तरह से असफल रही हैं। उसने शराबबन्दी, वैश्या बन्दी, चकबन्दी

[डा० राम मनोहर लोहिया]

और सोना बन्दी की है। मैं यह बताता हूं कि ये क्यों असफल रही हैं—

उपाध्यक्ष महोदय: यह अलग बात है।

डा० राम मनोहर लोहिया: ये सब जुड़ी हुई हैं। मैं ने यह चाहा था कि ये चारों बंदिया असफल हों। इसका कारण यह है कि सिद्धान्ततः ये ठीक थीं। लेकिन कहीं कोई दोष है। या तो अपने देश के पुराने-पने में या सरकार के चलन में जिससे ये चारों बन्दियां बिल्कुल अच्छी होते हुए भी असफल रही हैं और पूर्णतः असफल रही हैं। आगे के लिए देश को इससे कुछ नतीजे निकालने चाहियें। मैं समझता हूं कि देश में जो खराबिया हैं उनको दूर करने में तो कुछ समय लगेगा लेकिन जो इस सरकार की खराबी है जिससे यह चारों बन्दियां असफल रही हैं वह सोने के संबंध में श्री चिरंजी लाल गोयनका के मामले से बिल्कुल साबित हो जाती है। उनके यहां ग्यारह बारह लाख रुपये का सोना मिला था। कई दीवालें तोड़ कर मकान तोड़ कर। वह दिसम्बर 1965 में मिला था। उसके संबंध में जोधपुर यानी राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकदमा भी हुआ। उस मुकदमे का फैसला मई 1966 में हुआ। उस फैसले के खाली में दो वाक्य ही पढ़े देता हूं। कमबख्त यह फैसला अंग्रेजी में है। अंग्रेजी हमेशा दिक्कत पैदा करती है।

> "The application was ante-dated to create......"

इन साहब ने अपने बारह लाख रुपये के सोने को छिपाने के लिए एक झूठी बात यह कह दी कि यह सोना तो मैंने सरकार को चीन के युद्ध में अर्पित कर दिया था। और उसके लिए इन्होंने एक अर्जी भी दे दी। उस अर्जी के बारे में माननीय जज लोगों ने उच्च न्यायालय को लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय. रेजोल्यूशन के बारे में कुछ कहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया: अगर आपकी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। बैठ जाऊं? पता नहीं क्या चीज है। मैं यह कह रहा हूं कि यह सरकार कभी किसी अच्छे काम में सफल नहीं हो सकती है क्योंकि यह सरकार बड़े अपराधियों को छोड़ दिया करती है और छोटे लोगों को लाखों की तादाद में जेलों में डालती है और हजारों की तादाद में कत्ल करती है किसी न किसी रूप में इसलिए यह असम्भव है कि कोई भी भले काम में यह सफल हो जाए। यह बड़ा अपराधी है। यह 11-12 लाख रुपये का मामला है। इस व्यक्ति ने अर्जी दी—नकली अर्जी दी—कि इस ने यह सोना युद्ध के चन्दे के रूप में दिया था। जज का फैसला है कि यह अर्जी बिल्कुल नकली बनाई गई है क्योंकि जिस फार्म पर जिस कागज पर यह अर्जी दी गई है वह बाद की तारीख का है। इस के बावजूद इतने बड़े अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

· को छोड़ा कहां है?

डा० राम मनोहर लोहिया: क्या वह जेल में है? वह जेल में नहीं है। वह बाहर मजे से घूम रहा है।

श्री मधु लिमये (मूंगेर): वह तो इन का दोस्त है। क्या वह जेल में है?

श्री व० रा० भगत: वह बेल पर है।

डा० राम मनोहर लोहिया: बड़ा अपराधी हमेशा जमानत पर छट जाता है। एक बड़े अपराधी—डा० तेजा— के बारे में बार बार कहा जाता है कि उस से देश को कोई नुक्सान नहीं हुआ।

Shri K. C. Sharma: He is talking irrelevant things.

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर माननीय सदस्य जरा दिमाग को खोल कर रखे तो बात समझ में आ सकती है।

श्री ब० रा० भगत : डाक्टर साहब को समझ कर बात करनी चाहिए। उस को छोड़ा नहीं गया है। यह बात डाक्टर साहब गलत कहते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह सरकार जिस आदमी को जेल में रखना चाहती है अदालत चाहे उस को पचास दफा छोड़ दे सरकार उस को नजरबन्दी कानून में या किसी दूसरे कानून में जेल में रखती है।

श्री ब० रा० भगत : यह देश का कानून नहीं है। डाक्टर साहब का कानून होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह गलत कह रहे हैं। अदालत ने कहा है कि . . (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय क्या यह आदमी है ? यह सुनते नहीं हैं (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय यह क्या तरीका हो रहा है ? अगर सरकार अपने बारे में कोई दोष भी सुनना नहीं चाहती है तो आप इन लोगों को सुनने के लिए मजबूर कीजिए।

अदालत ने कहा है कि :

> "The application was ante-dated to create evidence in favour of the petitioner, but it did not strike him that the form which he was presenting therewith was of a later date and thus the trick sought to be played by the petitioner stands exposed."

यह चिरंजीलाल गोयनका के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है। उन लोगों की तरफ से कैसी कैसी ट्रिक्स चालें होती रहती हैं। वे विदेशी मुद्रा के करोड़ों रुपये हजम कर जाते हैं और फिर भी यहां मंत्री लोग कहा करते हैं कि नहीं उन से कोई नुक्सान नहीं हुआ। जयन्ती शिपिंग कम्पनी से सोना क्या हीरे और न जाने किन किन चीजों का करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ। लेकिन मंत्री कहते हैं कि नहीं हुआ। उस को यहां बुला नहीं सकते। कहते हैं कि पहले साबित करो कि उस ने कोई जालसाजी की है तब उस को बुलायेंगे। जब साबित हो जायेगा तो क्या उस के बाद दूसरा मुकदमा चलाया जायेगा ? आप अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खाली एक वाक्य सुन लीजिए।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. He must close now. Mr. Surendranath Dwivedy.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप केवल एक वाक्य सुन लीजिए।

Mr. Deputy-Speaker: He may please sit down.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप को अन्तर्राष्ट्रीय कानूम का एक वाक्य सुना देता हूं जो एक्स्ट्राडीशन के संबंध में है।

Mr. Deputy-Speaker: We are not concerned with all this. Order, order. He may please sit down.

डा० राम मनोहर लोहिया : इस का संबंध कैसे नहीं हैं ? यह सारे का सारा मामला सोने और विदेशी मुद्रा वगैरह का है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आखिर यह क्या चाहते हैं ?

Mr. Deputy-Speaker: He may please sit down. I have called Mr. Surendranath Dwivedy.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं बैठ तो जाता हूं लेकिन आप यह याद रखें कि अगर आप लोक सभा को इस तरह से चला कर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों

[डा० राम मनोहर लोहिया]

को हर किसी जालसाजी के ग्रारोप से बचाना चाहते हैं तो इस का नतीजा ग्रच्छा नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर स्वर्ण नियंत्रण कानून के शुरू से ग्राज तक के इतिहास को देखा जाये, तो यह बिल्कुल साफ हो जायेगा कि जब सरकार ने देश में स्वर्ण पर नियंत्रण करना तय किया, तो इस के पीछे न कोई नियत थी ग्रौर न कोई नीति थी। जिस तरह से 1963 से ले कर ग्राज तक स्वर्ण नियंत्रण के विभिन्न नियमों ग्रौर व्यवस्थाग्रों को बार बार बदला गया है, उस से भी यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस बारे में कल जो घोषणा की गई है, कुछ लोग उस पर बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह घोषणा किसी नीति के ग्राधार पर की गई है या सिर्फ चुनाव के ग्रवसर पर कुछ लोगों को खुश करने के लिए की गई है।

मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में कोई परिवर्तन न किये जाने का कारण सिर्फ पौलिटीकल ग्राब्स्टीनेशी था, गवर्नमेंट की जिद थी, इस के पीछे कोई पालिसी नहीं थी। मैं स्वर्णकारों को बधाई देता हूं कि जो काम पालियामेंट नहीं कर सकी, वह काम उन्होंने कर दिखाया उन्होंने गवर्नमेंट की जिद को उखाड़ कर फेंक दिया ग्रौर गवर्नमेंट को इस में परिवर्तन करना पड़ा।

प्रश्न यह है कि इस स्वर्ण नियंत्रण से फायदा किस को हुग्रा। छोटे छोटे सर्राफ खत्म हो गए, स्वर्णकर तबाह हो गए, बहुत से लोग मर गए ग्रौर इस के ग्रतिरिक्त सोने का दर भी नहीं घटा जोर न ही उस का स्मगलिंग बंद हुग्रा। हां, कुछ कप्ट ग्राफिशल्ज को थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुग्रा ग्रौर शायद इसी वजह से वे लोग इस को जारी रखना चाहते हैं। खैर, यह ग्रच्छा है कि स्वर्ण नियंत्रण को बहुत कुछ हटा लिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह भी बता दिया जाना जाये कि इस को हटाने के पीछ क्या नीति है ?

जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस बारे में कदम उठाया है, वह कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर टैक्स को हटा दिया, हालांकि हमारी इकानामी के लिए उस की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट ने कुछ हिसाब देते हुए इस का कारण यह बताया कि चूंकि एक्सपेंडीचर टैक्स से पर्याप्त कलेक्शन नहीं होता है, इस लिए उस को हटा दिया गया है। जहां तक प्रोहिबिशन का संबंध है, वह नाम के लिए चलता है, लेकिन उस में इल्लीगल तरीके से जैसे काम चल रहा है, वह ग्राप जानते ही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट एक्पेंडिचर टैक्स को हटा सकती है, तो स्वर्ण नियंत्रण को पूरे तौर पर हटाने के लिए उस के सामने क्या रुकावट है। मैं इस के खिलाफ़ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि देश में यह जो सोने का कारोबार चलता है, हमारी ग्रार्थिक व्यवस्था में उस की नियंत्रण की जरूरत है ग्रौर इस लिए उस पर उचित नियंत्रण कर के उस को चलने दिया जाये। प्राइमरी सोना जब्त कर लिया जाये।

गवर्नमेंट ने जो कमेटी मुकर्रर की है, उस ने ग्रभी ग्रपनी इन्टरिम रिपोर्ट दी है ग्रौर वह ग्रपनी फाइनल रिपोर्ट बाद में देगी। कमेटी ने कहा है कि गोल्ड कंट्रोल इस लिए कामयाब नहीं हुग्रा है कि रूल्ज का इम्प्लीमेंटशन ठीक तरह से नहीं किया गया है ग्रौर स्वर्णकारों के रोजगार का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं किया गया है। यह ग्राश्चर्य की बात है कि 27 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यह बात कही जाती है। ग्राखिर वह रुपया कहां गया ? उस में से स्वर्णकारों को कितना मिला? यह ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट सोचती है कि स्वर्णकारों को इतनी जल्दी दूसरे प्रोफेशन्ज में टाला जायेगा ग्रौर वे ग्रायरन ग्रौर ब्रास का काम करेंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट

देश में प्लानिंग के द्वारा अनएम्प्लायमेंट की समस्या को हल करना चाहती है और दूसरी तरफ वह एसा कानून बनाती है, जिस से अनएम्प्लायमेंट और भी बढ़ जायेगा।

एक बात के बारे में कई बार पूछा जाता है, लेकिन कोई उस को साफ नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब अपने भाषण में उस का जवाब दें। इस रिपोर्ट में कहा गया है :

> "Indeed, the recent devaluation of the rupee has created better conditions for the reduction of smuggling . . ."

—mark these words—

> " . . . and it would be most unfortunate if we are to compromise the basic objectives of gold control policy precisely at a time when a greater determination could pay rich dividends."

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात को साफ करे कि क्या वह स्वर्ण नियंत्रण में विश्वास करती है या नहीं। अगर गवर्नमेंट इस में विश्वास करती है, तो यह बिल्कुल साफ है कि उसकी तरफ से जो घोषणा की गई है वह सिर्फ इलेक्शन को दृष्टि में रख कर की गई है और जब इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आयेगी, तो वह दोबारा इस को लागू करेगी। अगर गवर्नमेंट इस में विश्वास नहीं करती है, तो कोई वजह नहीं है कि गोल्ड कंट्रोल का केवल मॉडिफिकेशन हो। उस अवस्था में उस को बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Now, the hon. Finance Minister.

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि. . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There can be no more speeches now. I have called the hon. Minister.

Shri Raja Ram: I had given my name but I have not been called. My party has not been represented.

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस से पहले कि वित्त मंत्री स्वर्ण नियंत्रण के बारे में अपने विचार प्रकट करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो छूट दी है, उस के लिए हम उस को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्वर्णकार देश भर में गिरफ्तार किये गये हैं, सरकार उन को छोड़ने के बारे में घोषणा करे और उन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया जाये।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. He cannot make a speech now.

17.00 hrs.

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और मुझे नाम ले कर पुकारा कि जो स्वर्णकार लोग देश में गिरफ्तार हुए हैं उन को गवर्नमेंट छोड़ दे। मैं गवर्नमेंट की ओर से सभा से कहूंगा कि स्वर्णकारों को छोड़ने का जो हुक्म है वह जारी हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक या दो रोज में सब छूट जायेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जिन लोगों ने गिरफ्तार हुए लोगों को जेल में मारा है उन को सख्त सजा दी जाये।

Shri Rajaram: My party has not been given any chance.

श्री बिशनचन्द्र सेठ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है कि मैं ने आप को लिख कर भेजा और बार बार कहा कि मैं इस सोने के काम का व्यापारी हूं। इस बात की कोई वजह नहीं है कि आप मुझको चान्स न दें। इस पूरे सेशन में मैं कभी नहीं बोला। आज पहली बार बोल रहा हूं और आप उस को चैक करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : आर्डर, आर्डर का क्या मतलब है। आप रोज आर्डर, आर्डर किया करते हैं और मैं ने इतनी बार सुन लिया। आखिर कोई रीजन होना चाहिये। पूरे सैशन में मैं एक बार भी नहीं बोला हूं। मैं आप को आज नोटिस भी दे चुका हूं कि मैं बोलना चाहता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry.

Shri Bishenchandar Seth: This is most unfortunate.

इस का क्या मतलब है कि आप मुझ को बोलने का टाइम नहीं देना चाहते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. No more speeches.

Shri Bishenchander Seth: मुझ को समय जरूर मिलना चाहिये था लेकिन इतना करने पर भी आप ने मुझे समय नहीं दिया।

I will leave the House.

Shri Bishenchander Seth then left the House.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Bhagat.

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय . . .

Shri Rajaram: One minute.

Shri Sezhiyan: Our group has not been given a chance.

Shri Rajaram: You have given chance to all other people, most of whom have been speaking in Hindi. You have not given a chance to our Group. You must hear me.

Mr. Deputy-Speaker: I am not allowing any more speeches.

Shri Sezhiyan: Only five minutes.

Shri Rajaram: I will talk in Tamil. You please hear me.

Mr. Deputy-Speaker: I am not allowing any more speech.

Shri Rajaram: We are a Group of 10 Members here. We must be heard.

Mr. Deputy-Speaker: You are unnecessarily obstructing the House.

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी ने .

Shri Rajaram: I want the Minister to talk in English. *(Interruptions)*.

श्री ब० रा० भगत : उपाध्यक्ष महोदय . .

Mr. Deputy-Speaker: You have got the translation also.

Shri Rajaram: Everybody is talking today in Hindi. You are not giving me a chance.... *(Interruptions)*.

श्री ब० रा० भगत : चूंकि प्रस्तावक महोदय ने हिन्दी में भाषण दिया है और हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों ने हिन्दी में भाषण दिया है खास तौर से माननीय सदस्य श्री द्विवेदी जी ने भी हिन्दी में भाषण दिया है तब मेरे लिये हिन्दी को छोड़ कर दूसरी भाषा में बोलना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

श्री राम सेवक यादव : आज ही नहीं, हमेशा यही होना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम पर बहस हुई और बड़े जोरदार शब्दों में माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये। आज यह मामला राजनीति से सम्बन्धित हो गया है, और खास कर के इस मौके पर जब चुनाव होने वाला है बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जायें, जो वाजिब भी नहीं हों, लागू भी नहीं हों और मौजूं भी न हों तो भी मेरे लिये कोई अचरज की बात नहीं है। मैं इसके औचित्य में नहीं जाना चाहता हूं, केवल जो वक्तव्य कल प्रधान मंत्री

जी ने इस अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में दिया है उसके बारे में थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं और उसके बाद जो हमारी आगे की कारवाई हैं और जो पृष्ठभूमि रही हैं उसके बारे में बतलाऊंगा । इससे अधिक समय मैं इस सभा का नहीं लेना चाहता ।

जो वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने दिया उसमें उन्होंने इन्फार्मल कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया । कल वक्तव्य इसलिये दिया गया कि कमेटी की रिपोर्ट और उनके वक्तव्य पर बहस करने के लिये जो कि आज हो रही हैं लोगों को कम से कम चौबीस घन्टे का समय मिल सके और उनको सारी बातें मालूम हो सकें । यह साफ कहा गया और अभी श्री द्विवेदी ने पूछा कि इस रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या राय है ? प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य में यह बात स्पष्ट है कि जिस आर्थिक और वित्तीय कारणों का हवाला उसमें दिया गया है उसके कारण अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि पिछले महीनों में या जब से यह नियन्त्रण लागू हुआ हैं इसको बदला जा सके । उस वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार उसको समझती हैं और उसको मानती है और फिर भी यह बात कही गई कि जैसा यह अधिनियम एक सामाजिक सुधार का कानून है मुख्यतः लेकिन हजारों सालों से यहां का सोने का प्रचलन और सोने के बारे में लोगों की जो आस्था थी और आदतें थीं उनको बदलने के लिये केवल कानून कुछ नहीं कर सकता । कानून मदद जरूर करता हैं मगर जब तक देश में जागृति न हो उसके पीछे लोगों की मनोभावना न हो, उनको बदलना आसान नहीं होता हैं ।

अभी कहा गया कि इस अधिनियम को चलते हुए तीन या साढ़े तीन साल हो गये लेकिन इस बीच में हम अपने उद्देश्य में सफलीभूत नहीं हुए, स्मर्गलिंग नहीं रुकी, सोने की कीमतें नहीं घटीं, सोने का व्यवहार कम नहीं हुआ । इसके लिये माननीय सदस्यों ने फैसला दे दिया ।

श्री ज० ब० कृपालानी : पहले क्यों नहीं ख्याल किया ।

श्री ब० रा० भगत : हजारों सालों से चली आने वाली बात के लिये यह सोच लेना कि तीन या साढ़े तीन साल में खत्म हो जायेगी यह ठीक नहीं हैं । फिर भी अगर इन तीन साढे तीन सालों की बात को देखा जाये मुख्य रूप से तो आप देखेंगे और इस रिपोर्ट में भी है कि सोने के बारे में लोगों का विचार यह हुआ है कि सोने का चलन कम होना चाहिये ।

खास बात यह है कि यहां पर कहा गया कि इस अधिनियम को वापस लेना चाहिये । बड़े जोर से इस बात को श्री मसानी ने कहा और श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी कहा . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : हिन्दुस्तान के रहने वालों ने कहा है ।

श्री ब० रा० भगत : इस समय सब से बड़ी अहमियत का सवाल यह है कि 100 करोड़ रु० का सोना आज छिपे तौर से देश में आता हैं । आज हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी हैं कि हम पैसे को बचा कर अपने देश के संयोजन में और विकास में लगाना चाहते हैं । मगर किसी भी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही कि क्या इसको वापस लेने से यह स्थिति बदल जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में एक बात कह सकता हूं कि चीप पापुलैरिटी के लिये आप महज एक राजनीतिक फायदा उठा लें चुनाव के मौके पर वह तो हो सकता हैं लेकिन जब देश के सामने इतना गहरा सवाल हैं, इतने बड़े सुधार की बातें हैं, लोगों के विचारों को बदलने की बात है, तब क्या यह जरूरी नहीं हैं कि इन चीजों पर हम जरा पार्टीबाजी से अलग हो कर इनको

[श्री ब० रा० भगत]

गहराई में उतरें । अभी भी यहां पर यह डिबेट हुआ . . . (व्यवधान) . . . मुझे कहने दीजिये । यहां बहस हुई । बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और कहा कि इस नियन्त्रण को वापस ले लेना चाहिये लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि आखिर 100 करोड़ रु० का जो सोना हमारे देश में आता है वह कैसे बन्द होगा । उनको इसकी फिक्र नहीं ह । . . (व्यवधान) . . उनको तो सिर्फ यह है . . .

Shri Umanath: You are not serious about getting the gold from the hoarders. What is the use of telling us?

श्री ब० रा० भगत : जो सुनार भाई आज विस्थापित हो गये हैं, जिनके सामने आज संकट आ गया है उनकी बात को उठाया गया . . . (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : तस्कर व्यापार बढ़ा है ।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक विस्थापित सुनारों का सवाल है उनके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं । उनको रोजी मिले, उनको काम मिले इसके लिये सरकार की तरफ से ऐलान हुआ, यह घोषणा हुई कि जो कुछ भी हो सकेगा किया जायेगा । . . . (व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker: We cannot go on like this.

Shri S. M. Banerjee: He may say anything he likes?

श्री ब० रा० भगत : मुझे कहने का हक है । . . . (व्यवधान) सच्चाई जरा दुखती है इसलिये माननीय सदस्यों को तकलीफ हो रही है मगर सच्चाई देश के लिये जरूरी है । चूंकि आज ऐसी स्थिति है वह बात सही है कि इसके लिये आन्दोलन भी हुआ, यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में यह बात उठी कि स्वर्ण नियन्त्रण से सुनार भाइयों को जो तकलीफ हो रही है उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके लिये कुछ किया जाये । आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने और हमारे कांग्रेस के भाइयों ने कहा वित्त मन्त्री जी ने भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और जो बयान कल हुआ उसमें यह बात साफ तौर से कही गई थी और मैं कहना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंट के और देश के सोचने की बात है कि आज जो विरोधी पार्टियां हैं वह महज अपने फायदे के लिये कहती हैं कि स्वर्ण नियन्त्रण हटाया जाये मगर उन को यह फिक्र नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति पर और दूसरी स्थितियों पर इसका क्या असर पड़ेगा । दूसरी तरफ यह बयान है (इंटरप्शन्ज़) मैं बैठने वाला नहीं हूं जब तक अपनी बात न कह लूं । दूसरी तरफ यह बयान है । उसके दो हिस्से हैं । इनको समझने की कोशिश करनी चाहिये । एक हिस्सा तो यह है कि चौदह कैरट सोने को हम इसलिए हटा रहे हैं कि हमारे जितने सुनार भाई हैं उनको पूरा काम करने का मौका मिले . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : पहले क्यों नहीं सोचा ?

श्री ब० रा० भगत : उनकी जो आज तकलीफें हैं वे दूर हों और उनको पूरा काम करने का मौका मिले । आपने जो गलतफहमी फैलाई है वह हट रही है इस वास्ते शायद आपको तकलीफ हो रही है । लेकिन जो सच बात है वह तो कहनी ही पड़ेगी ।

एक तरफ उनके सामने जो दिक्कत आई और खास तौर से काफी इसके बारे में वातावरण हुआ उसको मानते हुए हमने एक तरफ तो चौदह कैरट को हटाया जिससे आगे या निकट भविष्य में जो कोई भी काम करना चाहे सुनार का, स्वर्णकार का, जेवर बनाने का, उसका दिक्कत न हो और दूसरी तरफ जो बड़ी जरूरी चीज है और

जिसको मानना होगा वह यह है कि देश में आज जो स्मगलिंग चलता है जो तस्कर व्यापार चलता है . . .

श्री उ० म० त्रिवेदी : आन ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन सर . . .

श्री ब० रा० भगत : बाद में आप उठाइये । इस वक्त मुझे आप कह लेने दीजिये । सच्चाई क सुनने में तकलीफ क्यों होती है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : आप तो सत्य नारायण की कथा कर रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : सोने का जो तस्कर व्यापार चलता है उसको रोकने के लिये और उसको बन्द करने के लिए इसमें कारगर उपाय हैं । इसके सम्बन्ध में दो बातें इसमें हैं जिनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे । एक बात तो यह मानने की है कि हमारे देश में सोना नहीं होता है । केवल पांच हजार किलोग्राम ही होता है जो कि बिल्कुल हमारी जरूरतों को देखते हुए कम है । चाहें तो सोना बाहर से ला सकते हैं लेकिन हम लाने की स्थिति में नहीं हैं । इस वास्ते एक तरफ तो उसकी सप्लाई का सवाल है और दूसरी तरफ सोने को मंगाने का सवाल है । सोना देश में पैदा बहुत कम होता है बाहर से हम मंगा नहीं सकते हैं तो फिर कौनसा रास्ता हमारे सामने बच रहता है ? यह कहा गया है कि बाहर से आप विदेशी मुद्रा खर्च करके सोना मंगायें और दाम कम करें । लेकिन आज की स्थिति में यह सम्भव नहीं है । दूसरा तरीका यह है कि सोने की मांग को हम अपने देश में कम करें । जब तक देश में सोने की मांग को कम नहीं किया जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है । अब सोने की मांग को कम करने के दो तरीके हैं । एक तो इसकी मांग सरकारी तरीके से कम हो सकती है और सरकार जो कुछ कर सकती है वह करे और दूसर तरीका यह है कि देश में इसके पक्ष में वातावरण तैयार किया जाए । अब यह कहा गया है कि गांधी जी हमारे बीच में नहीं हैं । बात ठीक है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्लिमेंट तो है । गांधीजी की परम्परा तो है । पिछले पचास साल का हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास तो है । इसमें सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं । अगर लोहिया साहब इस पर विचार करें और दूसरे माननीय सदस्य विचार करें जिनकी कि देश में ख्याति है और देश में सोने का व्यवहार कम करने के लिए वातावरण तैयार करें तो यह देश की बड़ी भारी सेवा होगी बनिस्बत ऐसी गलत बातों को कहने के । हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि पार्लिमेंट का प्रत्येक मैम्बर देश के जनमत का अगुआ होता है । वह देश में जनमत को बनाता है । उसको देश में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये कि देश में सोने के जेवर पहनना, देश में जेवर का चलन, देश में जेवर का व्यवहार कम हो, मैं कहता हूं कि राजनीतिक आधार पर विरोध करने के बजाय अगर इसके बारे में वातावरण तैयार करते तो आज सोने की मांग कम होती ।

इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कदम इस बयान में जो कि प्रधान मन्त्री जी ने दिया है हमने उठाया है । वह कदम यह है कि जेवरों को छोड़ प्राइमरी गोल्ड जो है गट्टी का सोना है या बार्ज़ हैं और दूसरा है इसे कुछ दिनों के बाद रखने की किसी को छूट न हो किसी को अधिकार न हो । आप देखें कि अमरीका जैसे देश में भी जहां सोना प्रचुर मात्रा में है 150 डालरों के लगभग से ज्यादा आदमी सोना नहीं रख सकता है अगर रखता हैं तो उसको सजा होती है, जेल की सजा होती है । कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां प्राइमरी गोल्ड रखा जाए इस तरह से । यह भी कहा गया है कि सोने की रिफाइनरीज़ को हम

[श्री ब० रा० भगत]

राष्ट्रीयकरण करेंगे । यह भी एक बहुत बड़ा कदम है । मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्राइमरी गोल्ड को फोरफीट करो ।

श्री ब० रा० भगत : कानून में जो संशोधन हुआ है, वह दोनों बातों को पूरा करता है । एक तो कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था ने और उस के साथ साथ दूसरी संस्थाओं ने भी मांग की थी कि अभी चूंकि सामाजिक स्थिति ऐसी है कि स्वर्णकारों को पूरा काम नहीं मिल रहा है, उन के लिए बेशक सरकार ने बहुत कुछ किया है तो भी उन के पुनर्वास की समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई है, इस वास्ते उन की जो दिक्कत है, वह दूर हो और दूसरी तरफ तस्कर व्यापार को रोकने के सभी अंगों को हम अपने हाथ में मजबूत रखें और उस दिशा में एक के बाद दूसरा कदम आगे बढ़ायें और यही किया भी गया है ।

हमारे मसानी साहब ने कहा है कि रुपये का दाम गिर रहा है इसलिए सोने का दाम चढ़ रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इसको तो इकोनोमिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी पहले साल में ही जान लेता है । मैं उन से पूछना हूं कि उन के सामने कौन सा रास्ता है जिस से सोने का दाम गिर सकता सकता हो । उस के लिए उन्होंने कई सुझाव दिये हैं । उन्होंने कहा है कि प्लान बन्द कर दो, विकास बन्द कर दो, सब कुछ बन्द कर दो । देश की आबादी बढ़ती जाएं, देश की जरूरतें बढ़ती जायें , विकास का काम बन्द हो जाए, सोने के दाम कम हो जायें, यह जो उनका इकोनोमिक्स है, यह जो आर्थिक नीति उन्होंने बताई है , यह वही बता सकते हैं और वही इसको कह सकते हैं , मैं यह नहीं कह सकता हूं । इसको कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूं ।

इस वास्ते जो मौलिक बात हमारे सामने रह जाती है वह यह रहती है कि अभी की जो स्थिति है उस में हम को सुनारों को सभी सुविधायें प्रदान करनी चाहिये । लेकिन उन के साथ साथ यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिये कि जब तक सोने की मांग में कमी नहीं होगी, जेवर पहनने में कमी नहीं होगी, सोने का जो मोह है, उस में कमी नहीं होगी, तब तक सोने के दाम नहीं गिर सकते हैं । हमारे देश में सोना नहीं है और न हम लोग बाहर से ला सकते हैं । इसलिए एक तरफ तो हमें जनमत तैयार करना है । और उस में हमारे पालियामेंट के सभी माननीय सदस्यों और देश के सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है । और दूसरी तरफ कानून से उन सभी अंगों को जैसे रिफाइनरी का कंट्रोल करना, प्राइमरी गोल्ड पर बैन लगाना है, हमें मजबूत करना होगा और उस दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि हम सोने का चलन कम कर सकें और हमारे देश को आर्थिक रूप से जो इतना बड़ा आघात लगा है, उसकी हम पूर्ति कर सकें । प्रधान मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसकी यही रूपरेखा है । मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार ही है कि जिसने एक तरफ तो जनमत की मांग को माना है और दूसरी तरफ आज देश की जो स्थिति, है, देश की जो जरूरत है उस को सामने रखने में, उसको कहने में, हिचकी नहीं है, और न कभी ऐसा करने में हिचकती ही है केवल इसलिए कि चुनाव सामने हैं, चुनाव निकट हैं, हम कहेंगे कि हम को सोने के चलन को रोकना होगा और रोक कर आगे हमें सोने के तस्कर व्यापार को बन्द करना होगा । उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है और उस में हम सब का सहयोग चाहते हैं, उस में हमको सब की जरूरत है ।

मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है । यह देश का सवाल है । हम सब को इस नीति को मिल जुल कर आगे बढ़ाना चाहिए । मैं शास्त्रीजी से अपील करूंगा कि गोल्ड कंट्रोल वापिस लेने से काम नहीं चलता, अगर चलता होता तो मैं उन के साथ होता । चूंकि यह देश का सवाल है इस वास्ते उनको चाहिये कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको कार्य रूप देने के लिए आल इंडिया स्वर्णकार संघ की क्या मंत्री महोदय, बैठक बुलायेंगे, उन के लोगों से बातचीत करेंगे ताकि वे सैटिसफाई हो सकें ?

श्री ब० रा० भगत : मैं कई बार उन से मिल चुका हूं । उन से मेरी पहले मीटिंगें हो चुकी हैं । यह तो बाद की बात है । अभी तो उनको अपनी हंगर स्ट्राइक बन्द करने दीजिये । वे स्वस्थ हो जायें । इस के बाद इस पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को सरकार पूर्ण रूप से वापस ले लें इस आशय के मेरे प्रस्ताव को विरोधी पक्ष और कांग्रेस बैंचिज़ मे जिन माननीय सदस्यों ने अपना समर्थन दिया है, मैं उन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । केवल दो सदस्य इस प्रकार के थे, जिन्होंने प्रस्ताव की भावना का तो समर्थन किया, लेकिन अपने किसी पूर्वाग्रह के कारण वे इस से थोड़ा बिदक गए । वे सदस्य हैं श्री दीवान चन्द शर्मा और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ।

जहां तक श्री शर्मा का सम्बन्ध है, उन से तो कोई बहुत बड़ी शिकायत में इस लिए नहीं कर सकता हूं कि आखिर आदमी की अवस्था पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में एक बड़ी बात श्री शर्मा ने यह कही है कि हम तो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के पास होने के समय भी इस के विरोधी थे । मैं ने उसी समय लाइब्रेरी से लोक सभा की उस समय की कार्यवाही की किताब मंगाई, ताकि मैं देखूं कि वोटिंग में श्री शर्मा ने किस ओर अपना मत दिया था । कांग्रेसी भाइयों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वोटिंग के समय श्री शर्मा ने तो उन के पक्ष में थे और न हमारे पक्ष में थे, बल्कि वह उस समय लाबी में बैठे हुए थे ।

माननीय सदस्या, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि शास्त्री जी बड़ी मीठी भाषा में बोलते हैं । इस का उत्तर तो में उन के सहयोगी माननीया सदस्यया श्रीमती सहोदराबाई के शब्दों में ही देना चाहता हूं कि वह मुझ से भी मीठी भाषा में बोलती हैं । लेकिन प्रश्न यह है कि मीठी भाषा में आत्मा कितनी होती है । माननीय सदस्या की इस बात से कष्ट हुआ कि में ने बजाय मरहम लगाने के कड़वी बात क्यों कही । लेकिन यह शिकायत केवल उन की ओर से ही नहीं है बल्कि जब भी किसी मरीज़ का आपरेशन होता है, तो वह डाक्टर को गाली देता है लेकिन जब उसका घाव अच्छा हो जाता है तो वह डाक्टर को धन्यवाद और बधाई देता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के मन में मेरी बातों से कुछ कष्ट और कड़वाहट हुई हो उस पर मैं आश्चर्य प्रकट नहीं करता । लेकिन श्री भगत के भाषण पर मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ है । मेरा इस प्रकार

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

का स्वभाव है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के संचालन में जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उन में से कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में मेरी निजी प्रकार की धारणा है। मैं श्री भगत को उन व्यक्तियों में से समझता हूं, जो हमेशा इस सदन के सामने किसी भी बात का समुचित उत्तर ले कर आते हैं। लेकिन श्री भगत का आज का भाषण बिल्कुल इस प्रकार का था कि जैसे वह किसी चुनाव-सभा में भाषण दे रहे हों। मैंने अपने भाषण में कई स्पष्टीकरण चाहे थे, लेकिन श्री भगत ने उन का कोई उत्तर नहीं दिया है।

मैंने श्री भगत से यह पूछा था कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद सरकार को प्रति-वर्ष जो 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जो इन तीन सालों में लगभग 350 करोड़ हो जाता है, और 50 करोड़ रुपये के लगभग सरकार ने जो अनुदान दिया है, आखिर इन 400 करोड़ रुपयों की हानि की जिम्मेदारी किस पर है।

श्री ब० रा० भगत : ये आंकड़े कहां के हैं? मैंने तो जान-बूझ कर इस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह पता नहीं है कि श्री शास्त्री ये आंकड़े कहां से लाए हैं। यह बात मेरे दिमाग में नहीं घुसती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री भगत ने यह प्रश्न मुझ से पूछा कि मैं ये आंकड़े कहां से लाया। अगर इस सदन की सिलेक्ट कमेटी मंत्री महोदय के लिए कुछ प्रामाणिक हो सकती है, तो मैं उन से पूछूंगा कि क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद 27 करोड़ रुपये सालाना का इनकमटैक्स का घाटा हुआ है, स्वर्ण के व्यापार में लगे हुए लोगों पर राज्य सरकारों के द्वारा सेल्ज टैक्स, परचेज टैक्स और दूसरे प्रकार के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सिज लगे हुए हैं, उन सब को मिला कर 100 करोड़ रुपये प्रति-वर्ष का घाटा हुआ है।

श्री ब० रा० भगत : ये आंकड़े सिलेक्ट कमेटी में ज्युलर्ज और सर्राफ़े के आदमियों ने दिये थे। मैंने सेल्ज टैक्स के आंकड़े मंगाए हैं। सभी स्टेट्स में खाली सेल्ज टैक्स में कुल 55 लाख रुपये हुए, जब कि माननीय सदस्य 100 करोड़ रुपये की बात कह रहे हैं। इसी लिए मैंने जान-बूझ कर इस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे प्रसन्नता होती, अगर श्री भगत सेल्जटैक्स के अतिरिक्त इनकम टैक्स और अन्य टैक्सों के आंकड़े भी इस सदन के सामने रखते। वह सेल्ज टैक्स के आंकड़ 55 लाख रुपये बताते हैं—मैं 50 लाख रुपये मान लेता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद अगर इस देश को 350 करोड़ रुपये न सही, 100 करोड़ रुपये की भी हानि हुई, तो वित्त मंत्री इस बात का उत्तर दें कि इस हानि का ज़िम्मेदार विरोधी दल है या वह सरकार, जिस ने यह अधिनियम लागू किया। अगर श्री भगत इन बातों पर कुछ प्रकाश डालते, तो लगता वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं लेकिन उन्होंने सिवाये यह कहने के कि विरोधी पक्ष इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई नये तथ्य, आंकड़े या दलीलें नहीं रखीं।

अगर विरोधी पक्ष इस परिस्थिति का लाभ ठाना चाहते हैं और सरकार विरोधी पक्षों को यह अवसर नहीं देना चाहती है, तो, जैसा कि मैं ने सरकार से पूछा था, बम्बई में आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव आने के बाद सरकार

ने इस अधिनियम को वापस क्यों नहीं लिया ? अगर सरकार इस अधिनियम को उस समय वापस ले लेती, तो वह विरोधी पक्ष की इस आलोचना से बच सकती थी, विरोधी पक्ष को इस प्रकार की बहस उपस्थित करने का अवसर ही न मिलता और देश में सरकार की वाहवाही होती कि उस ने उपयुक्त समय पर निर्णय लिया है ।

मैंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि 1961 की जन-गणना के आंकड़ों के अनुसार इस देश में पांच लाख से ऊपर स्वर्णकार हैं और एल० पी० सिंह कमेटी के अनुसार तीन लाख स्वर्णकार हैं । जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिये हैं वह $2^1/_2$ लाख हैं । इस सम्बन्ध में मैंने यह पूछा था कि जब सरकार ने 22 और 24 कैरट के आभषण बनाने की छूट दे दी है, तो वित्त मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि उन ग़रीबों की स्थिति क्या होगी, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिये है और क्या वे सोने का काम कर सकेंगे या नहीं । वित्त मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था ।

श्री रामसहाय पाण्डेय : वे काम कर सकेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं समझता हूं कि चूंकि श्री रामसहाय पाण्डेय अभी फ़िनांस मिनिस्टर नहीं बने हैं, इस लिए अगर श्री भगत ही इस का जवाब दें, तो उस को कुछ महत्व दिया जा सकता है ।

श्री ब० रा० भगत : वे काम कर सकते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अब तो शास्त्री जी हमारी तारीफ़ करें । मंत्री महोदय, ने भी कह दिया है कि वे काम कर सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जहां तक वित्त मंत्री के इस कथन का प्रश्न है कि हमारे देश में सोने का मोह कम हो और इस के लिए सब को प्रयास करना चाहिए, मैं उन की इस भावना का हृदय से स्वागत करता हूं । यह दायित्व केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि हम इस देश में सोने के मोह को कम करें लेकिन मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं एक विशेष बात फिर कहना चाहता हू कि वह इस तथ्य को अपनी आंखों से ओझल न करें कि इस देश की नई पीढ़ी को ज़ेवरों के प्रति उतना मोह नहीं है, जितना कि पुरानी पीढ़ी को था । आज देश में जो लोग सोना एकत्रित कर के रखते हैं, वे केवल इस लिए ऐसा करते हैं कि सरकार जो काग़ज के नोट चलाती है, उस पर लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिये सोने की मुद्रा अपने पास रखते हैं ।

ऐसी स्थिति में देश को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से केवल हानि ही हुई है, उस को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है । सैकड़ों व्यक्ति मौत के घाट उत्तर गए और देश को अरबों रुपयों की हानि हुई । मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जो दलीलें दी हैं, उन में कोई ऐसी बात नहीं है, जिस से यह सदन संतुष्ट हो सके और इस लिए ऐसा कोई काणर नहीं है कि मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लू । मैं आप से आग्रह करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर मतदान लिया जाये, ताकि जो कांग्रेसी सदस्य स्वर्णकारों के हितैषी बनते हैं, उनकी कलई खुल सके ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : शास्त्री जो क्यों कलई खुलवाते हैं ?

Mr. Deputy-Speaker: I will now put the substitute motion of Shri Yashpal Singh to the vote of the House. The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that the restriction imposed on the manufacture of gold ornaments under

[Mr. Deputy-Speaker]

the Gold (Control) Act, be withdrawn immediately and financial assistance be given to the families of those goldsmiths who lost their lives while opposing this law and also that those goldsmiths who are in jails be released immediately." (5)

The Lok Sabha divided:

Division No. 29] AYES [17.33 hrs.]

Bade, Shri
Banerjee, Shri S.M.
Berwa, Shri Onkar Lal
Chatterjee, Shri H.P.
Gopalan, Shri A.K.
Gupta, Shri Priya
Kandappan, Shri S.
Karni Singhji, Shri
Laxmi Das, Shri
Limaye, Shri Madhu
Nambiar, Shri
Pattnayak, Shri Kishen
Rajaram, Shri
Ramabadran, Shri
Roy, Shri Saradish
Sezhiyan, Shri
Shastri, Shri Prakash Vir
Swamy, Shri M.N.
Trivedi, Shri U.M.
Umanath, Shri
Utiya, Shri
Vishram Prasad, Shri
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal, Singh, Shri

NOES

Achal Singh, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Alagesan, Shri
Alva, Shri Joachim
Babunath Singh, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan
Bal Krishna Singh, Shr
Balmikik, Shri
Barua, Shri R.
Basappa, Shri
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhakt Darshan, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrabhan Singh, Shri
Chaturvedi, Shri S. N.
Chaudhry, Shri Chandramani Lal
Chaudhuri, Shrimati Kamala
Chaudhuri, Shri Sachindra
Chavda, Shrimati Joraben
Dafle, Shri
Daljit Singh, Shri
Das, Shri B. K.
Das, Shri N. T.
Dass, Shri C.
Deshmukh Shri B. D.
Deshmukh, Shrimati Vimla
Dighe, Shri
Dorai, Shri Kasinatha
Gandhi, Shri V. B.
Gupta, Shri Shiv Charan
Haq, Shri M. M.
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri M. L.
Jadhav, Shri Tulshidas
Jagjivan Ram, Shri
Jedhe, Shri
Jena, Shri
Jyotishi, Shri J. P.
Khan, Dr. P. N.
Khanna, Shri Mehr Chand
Khanna, Shri P. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Kripa Shankar, Shri
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeo Prasad, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Maniyangadan, Shri
Mantri, Shri D. D.
Mathur, Shri Shiv Charan
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Melkote, Dr.
Minimata, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
More, Shri K. L.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Muthiah, Shri
Naik, Shri D. J.
Nanda, Shri
Niranjan Lal, Shri
Oza, Shri
Paliwal, Shri
Pande, Shri K. N.
Parashar, Shri
Patil, Shri D. S.
Pratap Singh Shri
Rai, Shrimati Sahodra Bai
Raj Bahadur, Shri
Rajdeo Singh
Ram Sewak Shri,
Ram Swarup, Shri
Ramanathan Chettiar, Shri R.
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganatha
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri Thirumala
Reddi, Dr. B. Gopala
Reddy, Shri H. C. Singh
Sadhu Ram, Shri
Saha, Dr. S. K
Sahu, Shri Rameshwar
Sarma, Shri A. T.
Satyabhama Devi, Shrimati
Shah, Shri Manabendra
Shashi Ranjan, Shri
Sheo Narain, Shri
Shree Narayan Das, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddananjappa, Shri
Siddhanti, Shri Jagder Singh
Sidheshwar Prasad, Shri
Singha, Shri G. K.
Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sinhasan Singh ,Shri
Soundaram Ramachandran, Shrimati.
Subramaniam, Shri C.
Swamy ,Shri M. P.
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D.N.
Tiwary, Shri R. S.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri
Upadhyaya, Shri Shiva Dutt
Vaishya, Shri M. B.
Verma, Shri Balgovind
Wadiwa, Shri

Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is: Ayes 24, Noes 111.

श्री यशपाल सिंह : मेरी लाइट नहीं आ रही है ।

***डा० राम मनोहर लोहिया :** हमारा वोट नहीं आया अध्यक्ष महोदय । हमारा भी गिन लीजिए ।

Mr. Deputy-Speaker : It will be noted.

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The next substitute motion is by Shri A. K. Gopalan.

Shri A. K. Gopalan: I do not press it.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his substitute motion?

Some hon. Members: Yes.

Substitute motion No. 4 was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The next one is by Shri Shree Narayan Das.

Shri Shree Narayan Das: I do not press it.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his substitute motion?

Some hon. Members: Yes.

Substitute motion No. 5 was, by leave withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The next one is by Shri Daji.

Shri Daji: It may be put to the vote.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that—

(a) the Gold (Control) Act and the relevant rules restricting the manufacture of ornaments above 14 carats be withdrawn forthwith;

(b) the bullion trade be nationalised;

(c) gold be made available to self-employed and certified goldsmiths; and

(d) financial and other assistance be given to the working goldsmiths to enable them to recover from the loss of livelihood caused to them by the Gold Control.". (6)

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The next one is by Shri Karni Singhji.

Shri Karni Singhji: It may be put to the vote.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"and adequate compensation be paid to goldsmiths who suffered losses as as result of this measure": (2)

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Now I am putting the main motion of Shri Prakash Vir Shastri to the vote of the House. The question is:

"That this House is of opinion that Gold Control be withdrawn and necessary steps in that regard taken by the Government immediately."

The Lok Sabha divided:

* Dr. Ram Manohar Lohia also wanted to vote for 'AYES'.

Division No. 30] **AYES** [17 37 hrs.

Bade, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Basant Kanwari, Shrimati
Berwa, Shri Onkar Lal
Chatterjee, Shri H. P.
Daji, Shri
Deo, Shri P. K.
Gopalan, Shri A.K.
Gulshan, Shri
Gupta, Shri Priya
Himmatsinhji, Shri
Kakkar, Shri Gauri Shankar
Kamath, Shri Hari Vishnu
Kandappan, Shri S.
Kapur Singh, Shri
Kar, Shri Prabahat
Karni Singhji, Shri
Krishnapal Singh, Shri
Laximin Das, Shri
Limaye, Shri Madhu
Lohia, Dr. Ram Manohar
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Pattnayak, Shri Kishen
Raja Ram, Shri
Reddy, Shri Yaliamanda
Sezhiyan Shr
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri Y.D.
Sinhga, Shri Y. N.
Swamy, Shri M. N.
Trivedi, Shri U. M.
Umanath, Shri
Utiya, Shri
Vishram Prasad, Shri
Warior, Shri
Yadav, Shri Ram Sewak
Y shpal Singh

NOES

Achal Singh, Shri
Akkamma Devi, Shrimati
Alagesan, Shri
Alva, Shri A. S.
Alva, Shri Joachim
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Bajaj Shri Kamalnayan
Bal Krishna Singh, Shri
Balmiki, Shri
Barua, Shri R.
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhakt Darshan, Shri
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrabhan Singh, Dr.
Chaturvedi, Shri S. N.
Chaudhry, Shri Chandramani Lal
Chaudhuri, Shrimati Kamala
Chaudhuri, Shri Sachindra
Chavda, Shrimati Johraben
Dafle, Shri
Daljit Singh, Shri
Das, Shri B. K.
Das, Shri N. T.
Dass, Shri C.
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shrimati Vimala
Dighe, Shri
Dorai, Shri Kasinatha
Gandhi, Shri V. B.
Gupta, Shri Shiv Charan
Haq, Shri M. M.
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri M. L.
Jadhav, Shri Tulsidas
Jagjivan Ram, Shri
Jedhe, Shri
Jena, Shri
Jyotishi, Shri J. P.
Khan, Dr. P. N.
Khanna, Shri Mehr Chan
Khanna, Shri P. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Koujalgi, Shri H. V.
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeo Prasad, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Maniyangadan, Shri
Mantri, Shri D. D.
Mathur, Shri Shiv Charan
Mehrotra, Shri Braj Bihari
Melkote, Dr.
Minimata, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
More, Shri K. L.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Muthiah, Shri
Naik, Shri D. J.
Nanda, Shri
Niranjan Lal, Shri
Oza, Shri
Paliwal, Shri
Pande, Shri K. N.
Parashar, Shri
Patil, Shri D. S.
Pratap Singh, Shri
Rai, Shrimati Sahodra Bai
Raj Bahadur, Shri
Rajdeo Singh, Shri
Ram Sewak, Shri
am Swarup, Shri
Ramanathan Chettiar, Shri R.
Rameshekhar Prasad Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganatha
Rao, Shri Thirumala
Re di, Dr. B. Gopala
Re dy, Shri H. C. Linga
adhu Ram, Shri
Sha, Dr. S. K.
Sahu, Shri Rameshwar
Sarma, Shri A. T.
Satyabhama Devi, Shrimati
Shah, Shri Manabendra
Shashi Ranjan, Shri
Sheo Narain, Shri
Shree Narayan Das, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddananjappa, Shri
Sidheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Sinhasan Singh, Shri
Soundaram Ramachandran, Shrimati
Subramaniam, Shri C.
Swamy, Shri M. P.
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri R. S.
Tula Ram, Shri
Uik Shri
Upadhayaya, Shri Shiva Dutt
Vaishya, Shri M. B.
Verma, Shri Balgovind
Wadiwa, Shri

Shri M. R. Masani: My light is not working.

Shri Surendranath Dwivedy: There is some defect in this; it is not working.

Dr. Saradish Roy: My vote has not been recorded.

Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is:

Ayes*	38
Noes	108

The motion is lost.

The motion was negatived.

Some hon. Members: Shame, shame.

17.37 hrs.

INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES†

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kishen Pattnayak.

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): Sir, I rise on a point of order. This half-an-hour discussion pertaining to the Institute of International Studies is being taken up in this House for the third time. It is a deliberate attempt to malign an institute of international repute for the simple reason that that institution has not accommodated some fanatic Hindi elements within the campus of that institution. The fact that a centrally sponsored university or an institution deemed to be a centrally sponsored one, simply because it is centrally sponsored....

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri S. Kandappan: I am coming to it. This is the first time I am raising a point of order in this House after I entered this House.

Mr. Deputy-Speaker: What is the rule or article that has been infringed?

Shri S. Kandappan: Simply because it is a central university or deemed to be a central institution it does not mean that the institution should give only scope for Hindi. The accident of the situation of the institution in some Hindi area....

Mr. Deputy-Speaker: You are arguing on merits.

Shri S. Kandappan: It is a question of academic freedom. It is a reputed institution which is serving the whole of India and not only my Hindi friends here. It is an institution for all of us. If they mean to denigrate or suppress an institution of its autonomy, it is not fair.

Mr. Deputy-Speaker: You have not shown me how there is any point of order arising. You have been speaking for the last five minutes.

Shri S. Kandappan: The dignity and decorum of this House demand that this kind of repeated attempt on the part of some Hindi imperialists just to have Hindi everywhere to the degradation......

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; there is no point of order. Shri Kishen Pattnayak.

Shri S. Kandappan: I pray that this should not be allowed to be taken up in this House.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Under what rule are you raising the point of order?

Shri S. Kandappan: Government has decided its policy. How can they bring it in the House repeatedly? *(Interruption)*

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There is no point of order.

श्री चन्द्र मणिलाल चौधरी (महुआ) : हिन्दी आपकी जबान नहीं है तो अंग्रेजी भी नहीं है ।

Shri S. Kandappan: Let my Hindi friends appreciate one point that when we use English in this House, it is not that English is our mother-tongue but it is in the larger interest of the national unity. We are graceful enough to tolerate proceedings in Hindi in the House. At least courtesy should be shown to us.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of orders. Shri Kishen Pattnayak.

---

*Shri M. R. Masani, Shri Surendranath Dwivedi and Dr. Saradish Roy also wanted to vote for "AYES".

†Half-An-Hour Discussion.